epaper.dehatsandesh.com

3 परगवाल क्षेत्र से आ रहे कई अवैध रेत से भरे डंपरों को किया जब्त

5 विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान: संन्यास वापस लिया

8 ढींगरी मशरूम की खेती

मौसम जम्मू — न्यूनतम 8, अधिकतम 17

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

देहात संदेश

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

वर्ष-22, जम्मू तवी, अंक-305 | जम्मू तवी, शनिवार 13 दिसम्बर, 2025 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

टेरर फंडिंग को रोकें, कट्टरपंथ का मुकाबला करें: सिन्हा

जनरल जोरावर सिंह को उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

श्रीनगर, 12 दिसंबर । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नौगाम विस्फोट में शहीद हुए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे। उपराज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है ताकि वे सुखी और सम्मानजनक जीवन जी सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले महीने आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करके आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसके लिए पूरा देश गर्व महसूस करता है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस की गहन जांच और आतंकी कृत्यों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनसे बचाव करने के बहुआयामी प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आतंकी वित्तपोषण के स्रोत को बाधित करने और कुछ अलगाववादी तत्वों द्वारा किए जा रहे कट्टरपंथीकरण के प्रयासों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का निर्देश भी अवसर पर विशेष महानिदेशक समन्वय पीएचक्यू एस.जे.एम. गिलानी; प्रधान सचिव गृह चंद्रकर भारती; एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार; उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी; संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग; आईजीपी कश्मीर वीके बर्डी; डीआईजी सीकेआर राजीव पांडे; एसएसपी श्रीनगर डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती; उपायुक्त श्रीनगर अक्षय लबरू और पुलिस एवं नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को वीर योद्धा, भारत के महानतम सेनापति और सैन्य रणनीतिकार जनरल जोरावर सिंह को उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराज्यपाल ने कहा कि जनरल जोरावर सिंह की दूरदृष्टि ने पीढ़ियों को प्रेरित किया और लोगों में जोश जगाया।

जम्मू में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने लद्दाख, बाल्टिस्तान, गिलगित और स्कार्दू में जनरल जोरावर सिंह के ऐतिहासिक सैन्य अभियानों का उल्लेख किया और डोगरा साम्राज्य के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं और समाज के सभी वर्गों से जनरल जोरावर सिंह के नैतिक स्पष्टता, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अटूट दृढ़ विश्वास और वंचितों को सशक्त बनाने के संदेश का अनुसरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए हम जीवन परिवर्तन के लिए स्वयं को समर्पित करें, युवाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करें और एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें।

उपराज्यपाल ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जनरल जोरावर सिंह के योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए, भारत सरकार ने एक उन्नत स्वदेशी हल्के टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह जी के नाम पर रखा है। जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह चेयर भी स्थापित की गई है। उनकी अद्वितीय सैन्य अभियानों और सामाजिक संगठन के दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए नई पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित प्रयास भी किए जा रहे हैं।

सरकार ने दी कोयले का निर्यात करने की मंजूरी

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। सरकार ने कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज इसके निर्यात को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोयले के निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग हेतु नीलामी नीति (कोल सेतु) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत फ्कोल सेतु विंडोफ्र नामक एक नयी विंडो बनाई गई है, जिससे कोयले का उपयोग किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए किया जा सकेगा। यह नयी नीति सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ती है।उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दीर्घकालिक आधार पर नीलामी हेतु कोयला लिंकेज का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए 2016 की गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में कोल सेतु नामक एक अलग विंडो जोड़ी गई है जिसमें कोयले की आवश्यकता वाले कोई भी घरेलू खरीदार लिंकेज नीलामी में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय संसाधन उद्योगों (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी की मौजूदा नीति के तहत सीमेंट, इस्पात (कोकिंग), स्पंज आयरन, एल्युमीनियम और अन्य (उर्वरक (यूरिया) को छोड़कर) सहित सभी नए कोयला लिंकेज का आवंटन एनआरएस को नीलामी के आधार पर किया जाएगा।

झ्वर्तमान एनआरएस लिंकेज नीति के अनुसार, उप-क्षेत्र केवल निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस विंडो के तहत प्राप्त कोयला लिंकेज का उपयोग स्वयं के उपभोग, कोयले के निर्यात या देश में पुनर्विक्रय को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य (कोयले की धुलाई सहित) के लिए किया जा सकता है।

खबर संक्षेप

राजौरी में व्हाइट नाइट कोर के जीओसी ने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की

जम्मू,12 दिसंबर। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जी.ओ.सी.), लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा, जीओसी रोमियो फोर्स के साथ, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025, को राजौरी जिले के मथियानिगला क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेना और क्षेत्र में तैनात सैनिकों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करना था। राजौरी, जम्मू कश्मीर के विभिन्न वरिष्ठ समाचार संवाददाताओं के अनुसार, कोर कमांडर को जमीनी स्थिति, आतंकवाद विरोधी ग्रिड, समन्वय तंत्र और भीतरी इलाकों में तैनात बलों की समग्र तत्परता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी इकाइयां सतर्क रहें और किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उन्होंने कर्मियों से उच्च परिचालन मानकों को बनाए रखने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों को जारी रखने का आग्रह किया।

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश, हथियार सहित घुसपैठिया गिरफ्तार

जम्मू, 12 दिसंबर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पारगवाल क्षेत्र में एक घुसपैठिए को पकड़ा है। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है।

बीएसएफ के अनुसार जवानों ने सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखते ही तुरंत कार्रवाई की और घुसपैठिए को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अब्दुल खालिक के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्ट पारगवाल (पुलिस स्टेशन खौर) को सौंप दिया गया है।

पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, ताकि उसके इरादों और किसी संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है।

राणा ने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की जनजातीय कल्याणकारी पहलों की सराहना की

जम्मू,12 दिसंबर। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025, को जम्मू स्थित गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट (जी.डी.सी.टी.) के मुख्यालय में ट्रस्ट के सदस्यों और प्रमुख सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत संवाद किया। ट्रस्टी सदस्यों के अलावा, बैठक में प्रमुख सामुदायिक प्रतिनिधि, शिक्षाविद, युवा नेता और अन्य महत्वपूर्ण हितधारक उपस्थित थे। उन्होंने गुर्जर-बकरवाल समुदाय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार, विमर्श किया और चल रही कल्याणकारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शैक्षिक उन्नति, युवा विकास, जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, छात्रावास एवं आवासीय सुविधाओं का विस्तार, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और जनजातीय बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। राणा ने उमर अब्दुल्ला सरकार की गुर्जर-बकरवाल समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सभा को आश्वस्त किया कि जीडीसीटी द्वारा प्रस्तुत सभी वास्तविक चिंताओं और प्रस्तावों को समय पर और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ गंभीरता से उठाया जाएगा। मंत्री ने ट्रस्ट की दशकों पुरानी सेवा विरासत की सराहना करते हुए हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने, शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने और गुर्जर/बकरवाल जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

जनगणना के लिए बजट मंजूर, पहली बार जातिगत गणना भी होगी

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्र सरकार 11,718.24 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ जनगणना 2027 कराएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके मुताबिक पहली बार जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनगणना का कार्य दो चरणों में किया जाएगा- पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में संपन्न होगा। पहली बार जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से डाटा इकट्ठा किया जाएगा और केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। जनगणना को विभिन्न मंत्रालयों को विविध उद्देश्यों के लिए स्पष्ट, मशीन रीडेबल और एक्शनेबल फॉर्मेट में उपलब्ध भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 का पहला

चरण- हाउसलिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलाया जाएगा। दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। हालांकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों और हिमाचल एवं उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह चरण सितंबर 2026 में संचालित किया जाएगा। पूरे देश में इस विशाल अभियान को पूरा करने के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें शिक्षक, पर्यवेक्षक और विभिन्न स्तरों के अधिकारी शामिल होंगे।

जम्मू-कश्मीर में SEC के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू

मिनिस्टर इट्टू को सिलेक्शन पैनल का मेंबर नॉमिनेट किया

श्रीनगर, 12 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मैक्सिमम एज बढ़ाने के लिए पास किए गए अमेंडमेंट को लोक भवन से मंजूरी मिलने के साथ, जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड को अपॉइंट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है - यह बॉडी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराने के लिए है। अथॉरिटी सूत्रों ने बताया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू को अपनी हेडिंग वाले सिलेक्शन पैनल के मेंबर्स में से एक के तौर पर नॉमिनेट किया है। सिलेक्शन पैनल में पंचायतों के इंचार्ज मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन और CM द्वारा नॉमिनेट किया जाने वाला एक सीनियर मिनिस्टर भी शामिल हैं। सकीना इट्टू के नॉमिनेशन के साथ, सिलेक्शन कमेटी अब बन गई है, और उम्मीद है कि सरकार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए LG को एक नाम रिकमेंड करने के लिए जल्द ही अपनी मीटिंग बुलाएगी। सूत्रों ने कहा, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग जल्द ही बुलाई जाएगी। राज्य चुनाव कमिश्नर को ष्टरू के नेतृत्व वाले सिलेक्शन पैनल की सिफारिश पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं।

J&K असेंबली ने पहले राज्य चुनाव कमिश्नर का पद संभालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने के लिए एक बिल पास किया था। बिल को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मंजूरी मिल गई है।

यह ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू-कश्मीर में अभी चुनी हुई पंचायतें और नगर पालिकाएं नहीं हैं। शहरी लोकल बॉडीज़ का कार्यकाल नवंबर 2023 में खत्म हो गया था, जबकि चुनी हुई पंचायतें 9 जनवरी, 2024 को खत्म हो गईं।

किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, यह अमानवीय होगा : शिवराज

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह अमानवीय होगा।पंजाब से आम आदमी पार्टी के संत बलबीर सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न में पूछा था कि पिछले 15 साल में देश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने उसका राज्यवार विवरण भी मांगा था।इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि एक भी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग-अलग पेशों में काम करने वाले आत्महत्या करते हैं।

उन्होंने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हरसंभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। वह अमानवीय होगा क्योंकि तब कितनी होती थी, अब कितनी होती है यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन हमारा संकल्प है कि एक-एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिये और उसमें हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। आत्महत्या के कई कारण होते हैं, कई बार विद्यार्थी भी कर लेते हैं, पेशेवर भी कर लेते हैं, व्यापारी भी कर लेते हैं, गृहिणियां भी कर लेती हैं। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चौहान ने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। साल 2014 की तुलना में उत्पादन 44 प्रतिशत बढ़ा है। सरकार उत्पादन की लागत घटाने के भी उपाय कर रही है।

जम्मू-कश्मीर के लिए 5 साल में कोई नया सरकारी अस्पताल नहीं

नई दिल्ली, 12 दिसंबर। केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में जम्मू-कश्मीर के लिए कोई नया सरकारी अस्पताल मंजूर नहीं किया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया। इसमें यह भी कहा गया है कि लद्दाख को 2025-26 के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 14.39 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले हैं, मिनिस्ट्री ने बताया। मिनिस्ट्री ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को 'ह।रू के बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट के तहत 2024-25 और 2025-26 दोनों के लिए ज़ीरो एलोकेशन मिला'। लद्दाख को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए 2024-25 में 1,274.33 लाख रुपये और 2025-26 में 1,439.05 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। इसने यह भी कहा कि नए अस्पताल बनाना मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ज़िम्मेदारी है, हालांकि केंद्र उन्हें NHM, PM-ABHIM, ECRP-II, PMSSY और 15वें फाइनेंस कमीशन ग्रांट जैसी योजनाओं के तहत मदद करता है।

डीजीसीए ने इंडिगो संकट मामले में चार अधिकारियों को किया बर्खास्त

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो संकट मामले में चार फ्लाइट ऑपरेशन्स इंस्पेक्टर (एफओआई) पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है।डीजीसीए के 11 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि ये अधिकारी तत्काल प्रभाव से डीजीसीए की सेवा से मुक्त कर दिये गये हैं और अपने मूल संगठनों में वापस चले जायेंगे।

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है। उनमें कंसल्टेंट (डिप्टी चीफ एफओआई) ऋषिराज चटर्जी, सीनियर एफओआई सीमा झमनानी, कंसल्टेंट (एफओआई) अनिल कुमार पोखरियाल और कंसल्टेंट (एफओआई) प्रियम कौशिक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द की गईं जिससे लोगों को भारी परेशानी का समाना करना पड़ा है। इसका असर अब तक देखा जा रहा है क्योंकि सरकार के दूरी के हिसाब से अधिकतम हवाई किराया तय करने के बाद भी टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं।

मुख्य सचिव द्वारा पी.एम. उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

जम्मू,12 दिसंबर। मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सर्दियों के महीनों के लिए कश्मीर घाटी में एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता का आकलन किया। बैठक सचिव, एफसीएस एंड सीए और संभागीय आयुक्त, कश्मीर के अलावा, बैठक में एफसीएस एंड सीए, जम्मू/कश्मीर के निदेशक और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे,

जिन्होंने पीएमयूवाई के नए विस्तारित चरण के तहत जिलेवार प्रगति, कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों और तैयारियों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने पीएमयूवाई के पहले चरण के प्रदर्शन की समीक्षा की और उपायुक्तों को पात्र लाभार्थियों के नामांकन में तेजी लाने, सदस्यता वाउचरों की संख्या बढ़ाने और ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ,के नवीनतम निर्देशों के मद्देनजर ई-केवाईसी को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके तहत लक्षित सब्सिडी का प्रसंस्करण ई-केवाईसी पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ओएमसी और जिला प्रशासन को 100ब्न ई-केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लाभार्थियों को उनकी हकदार सब्सिडी प्राप्त करने में देरी न हो।

बर्फबारी का मजा लूटना चाहते हैं तो, पटनीटॉप हैं आपके लिए पर्फेक्ट

पटनीटॉप-सनासर (जम्मू कश्मीर)। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार तथा चीड़ के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े सच में यहां आने वालों को नई दुनिया का आभास देते हैं। जिधर नजर दौड़ाएं, बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और उस पर दिखते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाते हुए लोग, जो देश के विभिन्न भागों से आए थे। यह है पटनीटॉप का प्रसिद्ध और मनमोहक पर्यटन स्थल जहां सिर्फ गर्मियां ही नहीं बल्कि सर्दियां भी मनोहारी होती हैं।

जम्मू से 108 किमी दूर पटनीटॉप का रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल समुद्रतल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है। लंबे लंबे चीड़ और देवदार के पेड़ हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो प्रकृतिप्रेमी हैं। साल भर इसकी खूबसूरत ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति रखती है।

जम्मू पर्यटन विभाग पटनीटॉप में बर्फ के खेलों का मजा आने वाले पर्यटकों को देने के लिए अगले कुछ दिनों में 'स्कीइंग फैस्टिवल' आयोजित करने जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में यह अपने किस्म का वार्षिक स्कीइंग फेस्टिवल होता है जिसमें पर्यटकों को स्कीइंग तो सिखाई ही जाती है और साथ ही पर्यटक बर्फ के खेलों का आनंद भी लूटते हैं।

जब कश्मीर में आतंकी घटनाओं ने देश-विदेश के पर्यटकों को गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मुख मोड़ने पर विवश किया तो उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्र बर्फ के खेलों के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब जम्मू क्षेत्र के 'पहलगाम' के रूप में जाने जाना वाला पटनीटॉप नए और महत्वपूर्ण बर्फ के पर्यटन स्थल के रूप में पूरी तरह से उभर चुका है।

पहलगाम के उपरांत पटनीटॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त करवाने में पर्यटन विभाग के जम्मू विंग का अच्छा खासा सहयोग रहा है। विभाग की मेहनत ही है कि आज पटनीटॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग करने वालों की भीड़ लगी रहती है। स्कीइंग के लिए तो पटनीटॉप की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी छोटी और बड़ी स्लोपों के साथ ही पटनीटॉप के साथ लगते नथाटाप क्षेत्र को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जो आप ही खूबसूरती की एक मिसाल है। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लोपों की तलाश तथा उनका विकास किया जा रहा है ताकि स्कीइंग के लिए आने वालों की भीड़ से निपटा जा सके।

आने वाले सभी लोगों को बर्फ के खेलों का आनंद उठाने का अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि स्कीइंग साल में सिर्फ सर्दियों के अढ़ाई महीनों में ही होती है। हिमाचल में यह सिर्फ दो महीने होती है पर पटनीटॉप व नत्थाटाप में यह कभी-कभी 3 महीनों तक होती रहती है क्योंकि बर्फ पिघलती नहीं है।

ऐसा भी नहीं है कि स्कीइंग न कर पाने वालों को पटनीटॉप आकर निराश होना पड़ता हो बल्कि कई बार लोग बर्फ पर फिसलने वाली लकड़ी की स्लेज का मजा लूटते हैं। कुछ लोग बर्फ के पुतले बना बर्फ के अन्य खेलों में लिप्त होते हैं। यह सब कुछ साल के सिर्फ अढ़ाई महीनों के दौरान ही इसलिए होता है क्योंकि बर्फ इसी दौरान रहती है और गर्मियों में पटनीटॉप आने वाले इन नजारों तथा अनुभवों से वंचित रहते हैं।

गर्मियों में आने वालों को निराशा होती हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि गर्मियों में पटनीटॉप आने का अपना ही अलग लुत्फ है जो कश्मीर के मुकाबले का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्रतल से जितनी ऊंचाई पर पटनीटॉप स्थित है उससे कम ऊंचाई पर श्रीनगर शहर है।

कश्मीर का मुकाबला करने वाले इस अनछुए पर्यटनस्थल पटनीटॉप में बर्फ के खेलों का एक रोचक पहलू यह है कि इसका आनंद उठाने वालों में अधिकतर वे लोग हैं जो पटनीटॉप से करीब अढ़ाई घंटों की यात्रा की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल माता वैष्णो देवी की गुफा के दर्शनार्थ आते हैं। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार पटनीटॉप आने वाले पर्यटकों में 80 प्रतिशत वैष्णो देवी के तीर्थयात्री ही हैं।

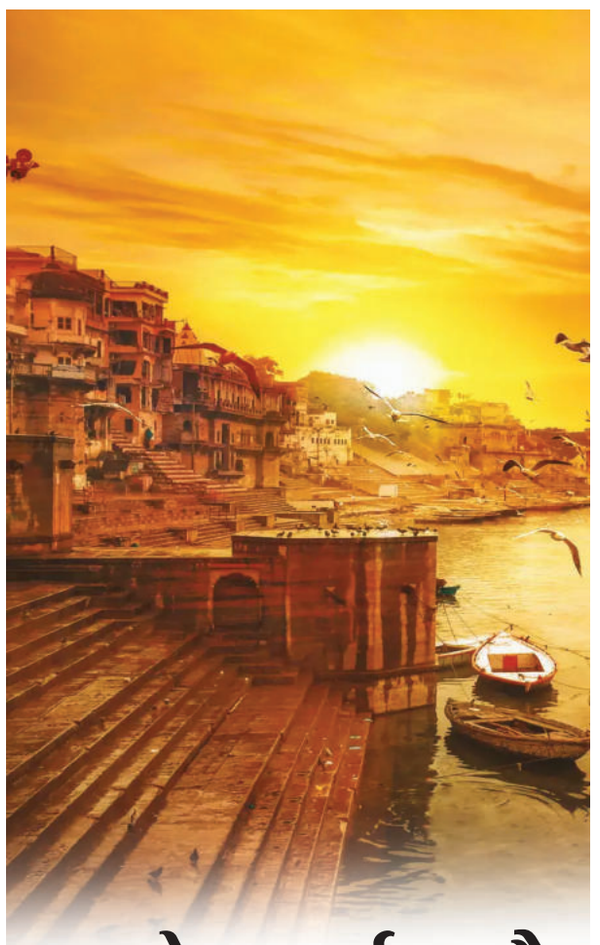

सबसे आकर्षक और बेहद खूबसूरत होती हैं इन जगहों की शाम

सुबह और शाम दिन के दो ऐसे प्रहर होते हैं, जब हमें जिंदगी के प्रति एक अलग सा लगाव महसूस होता है। हम में से कई लोग अपनी शाम पहाड़ो के बीच तो कोई नदी किनारे बीताना पसंद करता हैं। हममें से ज्यादातर लोग इन पलों को सुकून से प्रकृति के बीच महसूस करना चाहते हैं। आइए, आज उन चुनिंदा जगहों के बारे में जानते हैं, जहां की शाम बेइंतहा खूबसूरत होती है। हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर आप अपनी शाम बीता सकते हैं और वाकइ में इन जगहों की शाम का नाज़ारा काफी सुंदर और देखने लायक होता हैं। तो आई जानते हैं इन जगहों के बारे में -

बनारस - वाराणसी शहर में लोग आध्यात्मिक उपचार की तलाश में आते हैं और गंगा यहां सबसे सुंदर अनुभव प्रदान करती है। गंगा नदी के किनारे बैठे उगते सूरज का नजारा आपको गदगद कर देगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो नाव की सवारी भी कर सकते हैं। वैसे वाराणसी को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहां विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है।

राधानगर बीच, अंडमान - अंडमान में स्थित हैवलॉक द्वीप की शाम बहुत ही खूबसूरत होती है। यह सनसेट प्वाइंट प्राकृतिक सौंदर्य के कारण दुनियाभर में लोकप्रिय है। हैवलॉक द्वीप हनीमून के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे एशिया में सबसे बेस्ट सनसेट प्वाइंट माना जाता है। यहां पर जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रेल के बीच का हैं।

टाइगर हिल - यह सूर्योदय देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहता है। टाइगर हिल राजसी माउंट कंचनजंगा, और प्रतिष्ठित माउंट एवरेस्ट के मनोहारी दृश्य भी दिखाती है। अपनी शाम को यादगार बनाने के लिए यहां से अच्छी जगह और कोई नहीं हैं। दार्जलिंग जाने वाले पर्यटकों के लिए यह एक बहुत बड़ा आकर्षण हैं।

नंदी हिल्स - यहां पर आप वादियों के बीच लाल रंग के आसमान का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको एकांत पसंद करने वाले व्यक्ति हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम सही हैं। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अक्टूबर से जून में जा सकते हैं।

उमियम लेक - भारत के उत्तर पूर्व में स्थित यह झील सबसे शानदार स्थानों में से एक है। यह शिलांग से लगभग 15 किमी दूर स्थित है। जैसे ही सूरज उगता है और पहली किरणें झील के पानी को छूती हैं, आपको एहसास होगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हों।

नए साल पर इन जगहों पर घूमें, बजट भी नहीं बिगड़ेगा

नए साल का स्वागत करने के लिए अधिकतर लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन साथ ही उनके मन में यह भी होता है कि नए साल का स्वागत करने के चक्कर में कहीं उनका बजट ना बिगड़ जाए। कई बार तो लोग इस वजह से अपने घूमने का प्लान भी कैंसिल कर देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि नए साल में घूमने पर आपका बजट बिगड़ जाएगा तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप बजट में रहते हुए नए साल का स्वागत कर सकते हैं...

गोवा

नए साल पर घूमने की बात हो और गोवा का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो आप गोवा कभी भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन नए साल का जश्न गोवा में एक बेहद ही अलग तरह से मनाया जाता है। अगर आप यहां गए हैं तो बोहेमियन बीच पार्टी से लेकर नाइट क्लब इवेंट्स में जाएं। दिसंबर के आखिरी दिनों में गोवा में पार्टी का दौर चालू रहता है, ऐसे में आप यहां जमकर मस्ती कर सकते हैं। अगर आप गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का मन बना रहे हैं, तो टीटो क्लब, मैम्बो कैफे व बोट क्रूज पार्टी को एन्जॉय करें। अगर आप पहले से ही पैकेज बुक करवाते हैं तो आपको हर व्यक्ति का लगभग पांच से सात हजार रूपए खर्च आएगा।

ऊटी

अगर आप शोर-शराबे से दूर एक शांत जगह पर रहकर नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो आपको ऊटी जाना चाहिए। आप यहां पर आकर टी फैक्टी और म्यूजियम, बोटिंग, बोटेनिकल गार्डन में जाएं। साथ ही नए साल की फील लेने के लिए आप सड़कों पर निकल जाएं। वहां पर आतिशबाजी का माहौल देखकर आपके मन को यकीनन काफी अच्छा लगेगा। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपका खर्च सात से आठ हजार रूपए प्रति व्यक्ति आएगा।

पांडिचेरी

समुद्र तटों पर बाइक चलाने से लेकर छत पर बने कैफे में घूमने तक पॉन्डिचेरी आपको नए साल में एक अलग ही अनुभव महसूस कराएगा। खासतौर से, अगर आपका बजट काफी कम है और आप किसी बेहतरीन जगह पर घूमना चाहते हैं तो पांडिचेरी यकीनन आपकी जरूरत को पूरा करेगा। अगर आप वहां जा रहे हैं तो श्री अरबिंदो आश्रम, प्रोमेनेड बीच, हेरिटेज वॉक, विइट फ्रेंच कॉलोनी जाएं। यहां पर आपका प्रति व्यक्ति खर्च लगभग चार से पांच हजार आएगा।

आप भी हैं कैंपिंग के शौकीन तो जरूर जाएं इन बेहतरीन जगहों पर

क्या आपको हैं कैंपिंग करने का शौक और आप खोज रहे हैं कोई ऐसी जगह जगहां पर आप आराम से और शांत वातावरण में कैंपिंग कर पाएं तो आज हम आपके लिए लाएं है कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां पर आप आराम से और शांत वातावरण में कैंपिंग कर सकते हैं। नेशनल पार्क से प्राइवेट ग्राउंड तक यह हैं कुछ बहुत ही बेहतर जगह कैंपिंग करने के लिए। तो आईए जानते हैं इन जगहों के बारे में -

अलास्का-यह सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन कैंपिंग ग्राउंड्स में से एक हैं। यह जगह अलास्का के कूपर लैंडिंग में स्थित हैं। यह तीन कैंपसाइट लूप प्रदान करता है, जिनमें से एक झील पर है। यह वन्यजीवों के अवलोकन के लिए एक आदर्श स्थल है, जिसमें लायनक्स, भालू, गिलहरी और लॉन शामिल हैं। यहां पर जाने का सही समय मई से सितंबर का हैं।

अरिज़ोना-ग्रैंड कैन्यन-यह एक ऐसी कैंपिंग साइट हैं जो कि यहां के पर्यटकों के बीच काफी मशहूर हैं। यहां पर हर साल कई पर्यटक कैंपिंग करने आते हैं। रात के समय यहां का नज़ारा देखने लायक होता हैं। अगर आप यहां पर कैंपिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मार्च से मई और सितंबर से नवंबर आपके लिए एकदम सही समय हैं।

अर्कांसस-पेटिट जीन स्टेट पार्क-यह पार्क अर्कांसस का पहला स्टेट पार्क हैं। यह जगह अपने पर्यटकों के 125 कैंपिंग साइट्स प्रदान करती हैं। यह जगह परिवार के साथ जाने के लिए काफी अच्छी हैं। यहां पर आपको मछली पकड़ना, स्विमिंग पूल, प्लेगाउंड, टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां पर और भी कई खूबसूरत जगह भी हैं। यहां पर जाने का सही समय अक्टूबर से नवंबर क बीच का हैं।

कैलिफोर्निया-योसेमाइट नेशनल पार्क-वैसे तो कैलिफोर्निया में घूमने के लिए कई सारे नेशनल पार्क्सहैं लेकिन यह पार्क कैलिफोर्निया का सबसे मशहूर पीर्क हैं। बता दें कि इस पार्क को यूनेस्कों की सूची में भी शामिल किया गया हैं। यहां पर आपकोसिकोइया के पेड़ और झरनों क बीच अपना समय बीताने का मौका मिलेगा। आपको यहां पर कैंपिंग करने के लिए पहले से ही रिसर्वेशन करना हेगा। अगर आप यहां पर कैंपिंग करने जाना चाहते हैं तो आपको मई से अक्टूबर और नवंबर से दिसंबर क बीच जाना चाहिए।

मिनेसोटा-स्प्लिट रॉक लाइटहाउस स्टेट पार्क-यहां पर आपको काफी सारे पर्यटक मिल जाएंगे यह कैंपिंग करने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा स्थल हैं। इसलिए अगर आप यहां पर कैंपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने लिए पहले से ही रिसर्वेशन कर लें। यहां कई पर्यटक कैंपिंग के साथ साथ हाइकिंग और फिशिंग भी करने आते हैं। यहां पर जाने का सही समय जून से अगस्त के बीच का हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जिले में आवारा पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण उपायों पर हुई समीक्षा बैठक

कठुआ, 12 दिसंबर (हि.स.)। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने जिले भर में आवारा पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान डीसी ने सभी जिला अधिकारियों विशेष रूप से नगर पालिका, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवारा पशुओं की सुरक्षा, प्रबंधन और देखभाल के लिए अपनी निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। डीसी ने अधिकारियों को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें सीमा दीवारों की स्थिति, उचित द्वार संरचनाओं, चैकीदारों की उपलब्धता और आवारा पशु प्रबंधन प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक कार्यालय के लिए नामित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख हो। एडीसी, एसडीएम और नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारियों को स्थानीय निकायों और संबंधित हितधारकों के परामर्श से कुत्तों को चारा खिलाने के लिए निर्धारित स्थानों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियमित रूप से चारा खिलाने के केंद्र आवारा कुत्तों की आबादी की व्यवस्थित निगरानी और बेहतर प्रबंधन में सहायक होंगे।

अनुच्छेद 51(ए) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर व्याख्यान आयोजित

कठुआ, 12 दिसंबर (हि.स.)। शिक्षित भारत अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महानपुर में राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रेणु बाला द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर व्याख्यान दिया गया।

सत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(ए) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया जो नागरिकों को संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने, सद्भाव को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समाज में जिम्मेदारीपूर्ण योगदान देने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। प्रोफेसर रेणु बाला ने समझाया कि कैसे ये कर्तव्य जिम्मेदार नागरिकता की नैतिक नींव बनाते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। व्याख्यान का उद्देश्य इन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना और छात्रों एवं कर्मचारियों को दैनिक जीवन में इनका पालन करने में अपनी भूमिका को समझने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में प्रोफेसर मोहिंदर नाथ शर्मा, प्रोफेसर सपना, प्रोफेसर रेणु, प्रोफेसर अंबिका, प्रोफेसर हिलाल, प्रोफेसर शीतल, प्रोफेसर मीनू, रमेश, कुलदीप और मंगू राम सहित सभी संकाय और कर्मचारी सदस्य उपस्थित थे। लगभग 50 छात्र भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समन्वय प्रधानाचार्य डॉ. संगीता सूडान के मार्गदर्शन में निशा कुमारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन पुस्तकालयाध्यक्ष निशा कुमारी द्वारा दिए गए धन्यवाद भाषण के साथ हुआ।

असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रियगोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट की बिक्री पर लगाया सख्त प्रतिबंध

अनंतनाग, 12 दिसंबर (हि.स.)। प्रयोगशाला परीक्षणों में उत्पाद को उपभोग के लिए असुरक्षित पाए जाने के बाद अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रियगोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट (बैच संख्या ई25केपीओ2एफबी) की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

अनंतनाग के खाद्य सुरक्षा विभाग के नामित अधिकारी के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित बाजार निरीक्षण के दौरान बिस्कुट ब्रांड के नमूने की जांच के बाद की गई है। नमूना गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया था जहां विश्लेषकों ने रिपोर्ट संख्या जेके-665/डीईसी/25/786 दिनांक 05-12-2025 में सल्फाइट का स्तर अधिकतम अनुमेय सीमा से अधिक पाया।

अधिकारियों ने बताया कि अनुमोदित सीमा से अधिक सल्फाइट सामग्री वाले खाद्य उत्पादों का सेवन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थों

का निर्माण या बिक्री सख्त वर्जित है। एफएसएसए की धारा 36(3)(बी) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामित अधिकारी शेख ज़मीर अहमद ने अनंतनाग जिले में उक्त बिस्कुट बैच की बिक्री पर अगले आदेश तक तत्काल रोक लगा दी है। विभाग ने व्यापारियों, दुकानदारों और वितरकों को सलाह दी है कि वे उत्पाद को दुकानों से हटा लें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

'स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है'

जम्मू, 12 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के 99.31त्न गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है । स्वच्छ भारत मिशन जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और स्वच्छ भारत मिशन को एक प्रभावी कार्यान्वयन ने स्वच्छता को पूरे देश में एक जन आंदोलन में बदल दिया है।

इस दिशा में जम्मू-कश्मीर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता और पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर राम रतन ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 99.31त्न गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है जो स्वच्छता के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण है। बलबीर राम रतन ने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कुल 6216 गांवों में से 6173 गांवों को अब ओडीएफ प्लस मॉडल श्रेणी में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि स्वच्छता के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता और जनता की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि यह सफलता मोदी सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता और जन कल्याणकारी प्रकृति का स्पष्ट प्रमाण है।

पुलिस ने चोरी के दो मामले सुलझाए, 9 तोले सोना बरामद, चोर गिरफ्तार

कठुआ, 12 दिसंबर (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा के नेतृत्व में दो चोरी के मामलों को सुलझाया है जिसमें 9 तोले सोना बरामद कर एक चोर को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे मामले में एक चोरी हुई गाड़ी बरामद की है।

डीएसपी मुख्यालय रविंद्र सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर 2025 को खुशी चौधरी पत्नी विशाल कुमार नामक एक महिला ने हटली पुलिस चैकी में चोरी की एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद हटली प्रभारी शुभम महाजन के नेतृत्व में हटली पुलिस टीम ने भारी मशक्कत और डिजिटलाइजेशन के तौर-तरीके अपनाकर इस मामले को सुलझाया और एक युवक अंकुश शर्मा पुत्र भारत भूषण निवासी वार्ड नंबर 13 हटली मोड को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला और चोरी हुआ सोना बरामद किया गया।

दूसरे मामले में राणा पुत्र मलकीत सिंह निवासी जंडियल ने कठुआ थाना में अपनी पिकअप गाड़ी की चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने वीरू नामक युवक को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया और गाड़ी बरामद की गई। कठुआ पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब भी कभी शादी समारोह या घर से बाहर जाएं तो विशेष तौर पर अपने सोने के जेवर अपने बैंक के लॉकर में जमा करवाएं और अपने घरों में सीसीटीवी जरूर लगाएं। अगर घरों में सीसीटीवी नहीं है तो अपने आस-पड़ोस को सूचित करके जाएं ताकि चोरी जैसी बढ़ती वारदातों पर लगाम लग सके।

तालाब में गिरने से बच्चे की मौत

शोपियां, 12 दिसंबर हि.स.। शुक्रवार को चोटीपोरा इलाके से एक दुखद घटना की खबर आई जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जब वह गलती से अपने घर के पास एक तालाब में गिर गया।

अधिकारियों ने बताया कि चेक चोटीपोरा शोपियां के रहने वाले ज़ाकिर अहमद कोहली के बेटे मेहरान ज़ाकिर के तौर पर पहचाने गए बच्चे की पास के तालाब में फिसलकर मौत हो गई।

परगवाल क्षेत्र से आ रहे कई अवैध रेत से भरे डंपरों को किया जब्त

अखनूर, 12 दिसंबर (हि.स.)। डीएमओ नवीन कुमार और उनकी टीम ने परगवाल क्षेत्र से आ रहे कई अवैध रेत से भरे डंपरों को जब्त किया। इन्हें खुग्गा मोड़ के पास रोका गया। डीएमओ की टीम की त्वरित कार्रवाई की व्यापक रूप से सराहना की गई है क्योंकि उन्होंने अवैध खनन और रेत के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

हालांकि इस घटना ने गंभीर चिंताएं भी पैदा की हैं। परगवाल से खुग्गा जाने वाले मार्ग पर कई पुलिस चौकियां होने के बावजूद वहां तैनात अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे वाहन बिना जांच के गुजर गए। यह चिंता का विषय है कि इन डंपरों को डीएमओ नवीन कुमार और उनकी टीम द्वारा जम्मू से यात्रा करने और अंतत खुग्गा नंबर 4 के पास उन्हें रोकने के बाद ही रोका जा सका।

डीएमओ की टीम द्वारा किया गया प्रभावी अभियान अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है और उनके प्रयास प्रशंसा के पात्र हैं।

पुलिस स्टेशन आर.एस. पुरा, ने लापता महिला का पता लगाया , उसके परिवार से मिलाया

जम्मू, 12 दिसंबर (हि.स.)। 10.12.2025 को जिला जम्मू निवासी एक महिला (नाम छिपाया गया) की गुमशुदगी की रिपोर्ट डीडीआर नंबर 024 दिनांक- 09-12-2025 के तहत उसके पति की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी और लापता महिला का पता लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था।

इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ पुलिस स्टेशन आर.एस. पुरा, इंस्पेक्टर अरएस परिहार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत की और तकनीकी सहायता की मदद से पुलिस टीम द्वारा उक्त लापता महिला का पता लगाया गया और सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उक्त लापता महिला को अब उसके परिवार के साथ फिर से मिला दिया गया और कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया।

बुलबुल नाग झरना लगातार दूसरे साल भी सूखा, आस-पास के कई गांवों में पानी की भारी कमी

श्रीनगर 12 दिसंबर (हि.स.)। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के नेवा इलाके में ऐतिहासिक बुलबुल नाग झरना लगातार दूसरे साल सूख गया है जिससे आस-पास के कई गांवों में पानी की भारी कमी हो गई है जो लंबे समय से पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए इस पर निर्भर थे। झरने के सूखने से जो कभी अपने भरपूर, शीशे की तरह साफ बहाव के लिए जाना जाता था। लोग परेशान हैं क्योंकि उनका कहना है कि पानी के दूसरे इंतज़ामों के लिए उनकी गुज़ारिशें अनसुनी कर दी गई हैं। नेवा, परिगाम, काकापोरा और दूसरे प्रभावित इलाकों के स्थानीय लोगों ने कहा कि हालात बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं। नेवा के रहने वाले मुश्ताक अहमद ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बुलबुल नाग इस हालत में पहुँच जाएगा। इस झरने से हज़ारों लोगों को खाना मिलता था। अब हमें पानी के टैंकरों का इंतज़ार करना पड़ता है जो कई दिनों बाद आते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद पानी की सप्लाई सिस्टम को ठीक करने या दूसरे स्त्रोत बनाने के लिए कोई लंबे समय के उपाय नहीं किए गए हैं। एक स्थानीय महिला मुमताज़ ने कहा कि पिछले साल अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि वे पानी की सप्लाई के दूसरे विकल्प देखेंगे लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला है और हमें हर बाल्टी ध्यान से स्टोर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह रोज़ की लड़ाई बन गई है।

सीएसआईआर नेट के अभ्यर्थियों ने भेदभाव का आरोप लगाया

श्रीनगर, 12 दिसंबर(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर आगामी सीएसआईआर नेट परीक्षाओं के लिए अपने परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के इच्छुक उम्मीदवारों में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। इस कदम ने उन उम्मीदवारों को उतेजित कर दिया है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके लिए बाधाएं पैदा करने के लिए उनके केंद्र जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर निर्धारित किए गए हैंद्य नेट परीक्षा 18 दिसंबर को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाएगी यूजीसी द्वारा अधिकृत परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था जो 2018 से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित है। दयनीय बात यह है कि कई छात्रों के केंद्र दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में हैं। यह जम्मू-कश्मीर के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है एक अभ्यर्थी ने बताया

एलजी कविंदर गुप्ता ने पूगा जियोथर्मल और पैंग सोलर प्रोजेक्ट्स का दौरा किया

लेह, 12 दिसंबर। लद्दाख के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, श्री कविंदर गुप्ता ने दो बड़े क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू करने के लिए चांगथांग इलाके का दौरा किया – पूगा में 1 MW का जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जिसे ONGC चला रहा है और पैंग में 11GW का सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसे SECI चला रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के मुताबिक, लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल इलाका और रिन्यूएबल एनर्जी का नेशनल हब बनाने के विज़न को पूरा करने में बहुत ज़रूरी हैं। पूगा हॉट स्प्रिंग्स में, जो चल रहे 1 MW के जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट की साइट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया गया कि 450 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में 600 मीटर की और ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी। जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए दो थर्मल कुएं बनाए जा रहे हैं, और यह भी बताया गया कि शुरुआती अनुमानों के उलट, इस प्रोजेक्ट से 1 MW के बजाय लगभग 4 MW बिजली बनने की उम्मीद है। बनी हुई बिजली को ग्रिड में जोड़ा जाएगा और आस-पास के गांवों में घरेलू इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाएगा, जिससे यह देश में अपनी तरह का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट बन जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, डॉ. पवन कोटवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुमाथांग और पुगा में गर्म पानी के झरनों के दवा वाले गुणों के बारे में बताया और बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों और विज़िटर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए गर्म पानी के झरनों वाली जगहों पर गर्म और ठंडे नहाने की सुविधाएं बनाने की योजना बना रहा है।

रेलयात्री कृपया ध्यान दें!

महत्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाडियां संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी सं. 02417/02418 प्रयागराज – नई दिल्ली – प्रयागराज विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी | 03 फेरे

गाड़ी सं. 02417		स्टेशन	गाड़ी सं. 02418	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
---	23:20	प्रयागराज	04:30	---
11:40	---	नई दिल्ली	---	14:00

चलने के दिन: 02417 प्रयागराज से दिनांक 14.12.2025 को और 02418 नई दिल्ली से दिनांक 13.12.2025 एवं 15.12.2025 को।

ठहराव: फ़तेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा जं., टूण्डला जं. एवं अलीगढ जं. स्टेशन।

स्थान: प्रथम वाता., वाता. 2 टियर, वाता. 3 टियर, वाता. 3 टियर इकॉनोमी, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

रेलगाड़ी सं. 04081/04082 नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – नई दिल्ली विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी | 03 फेरे

गाड़ी सं. 04081		स्टेशन	गाड़ी सं. 04082	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
---	23:45	नई दिल्ली	10:00	---
12:00	---	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	---	21:20

चलने के दिन: 04081 नई दिल्ली से दिनांक 13.12.2025 को एवं 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से दिनांक 13.12.2025 और 14.12.2025 को

ठहराव: पानीपत जं., कुरुक्षेत्र जं., अंबाला छावनी, लुधियाना जं., जलंधर छावनी, पठानकोट छावनी, जम्मू तवी, शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन।

स्थान: वाता. 3 टियर इकॉनोमी एवं सामान्य श्रेणी।

रेलगाड़ी सं. 04062/04061 दिल्ली सराय रोहिल्ला – साबरमती – दिल्ली सराय रोहिल्ला विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी | 08 फेरे

गाड़ी सं. 04062		स्टेशन	गाड़ी सं. 04061	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
---	08:10	दिल्ली सराय रोहिल्ला	23:30	---
00:30	---	साबरमती	---	05:15

चलने के दिन: 04062 दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिनांक 21, 24, 27 एवं 30.12.2025 को और 04061 साबरमती से दिनांक 22, 25, 28 एवं 31.12.2025 को।

ठहराव: दिल्ली छावनी, गुड़गांव, रेवाड़ी जं., अलवर जं., बांदीकुई जं., गांधीनगर जयपुर, जयपुर जं., किशनगढ़, अजमेर जं., ब्यावर, मारवाड़ जं., फालना, आबू रोड एवं पालनपुर जं. स्टेशन।

स्थान: प्रथम वाता., वाता. 2 टियर, वाता. 3 टियर, वाता. शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

रेलगाड़ी सं. 08403/08404 पुरी – दिल्ली जं. – भुवनेश्वर विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी | 02 फेरे

गाड़ी सं. 08403		स्टेशन	गाड़ी सं. 08404	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
---	11:45	पुरी	---	---
13:30	13:35	भुवनेश्वर	06:30	---
20:30	---	दिल्ली जं.	---	23:00

चलने के दिन: 08403 पुरी से दिनांक 15.12.2025 को और 08404 दिल्ली जं. से दिनांक 16.12.2025 को।

ठहराव: खोरधा रोड (केवल रेलगाड़ी संख्या 08403 के लिए), भुवनेश्वर, कटक जं., जाजपुर केन्दुझर रोड, भद्रक, बालेश्वर, जालेश्वर, हिजली, मेदिनीपुर, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, आद्रा जं., नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमोह, पारसनाथ, कोडरमा, गया जं., डेहरी ऑनसोन, सासाराम जं., पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., मिर्जापुर, प्रयागराज जं., फतेहपुर, गोविंदपुरी, टूण्डला जं. एवं अलीगढ़ जं. स्टेशन।

स्थान: वाता. 2 टियर, वाता. 3 टियर, वाता. शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES ऐप देखें।

पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा—हमारा ध्येय

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

पुलिस ने मढ़ गोलीबारी की घटना को सुलझाया, डोमाना में 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

जम्मू, 12 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने कुछ दिन पहले मढ़ इलाके में हुई गोलीबारी की घटना को सुलझाकर सभी 05 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

जम्मू के मढ़ निवासी जतिंदर सिंह उर्फ राजन ने पुलिस स्टेशन दोमाना में एफआईआर संख्या 258/2025 के तहत शस्त्र अधिनियम की धारा 3/4/25/27 और धारा 191(2) बीएनएस के तहत अपराध से संबंधित मामला दर्ज किया।

इंस्पेक्टर वरुणेश्वर, एसएचओ दोमाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की और घटना में शामिल रिपु दमन सिंह जम्वाल पुत्र शुभदीप सिंह जम्वाल निवासी मुबारक मंडी, अक्षय शर्मा पुत्र स्वर्गीय राजेश शर्मा निवासी रगुनाथ पुरा जम्मू, विक्रांत केसर पुत्र स्वर्गीय राकेश केसर निवासी मढ़ जम्मू, रोहन गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय मोहिंदर पाल निवासी गुज्जर नगर,

अभिनेश सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी डोगरा हाल रेहारी जम्मू को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 01 देशी पिस्तौल (कट्टा) साथ में एक जिंदा राउण्ड और एक फायर किया हुआ राउण्ड व चार धारदार हथियार भी बरामद किये गये ।एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, दोनों का इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने में किया गया था।

पुलिस ने बिना स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के खिलाफ शुरू किया एक विशेष अभियान

श्रीनगर, 12 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को बिना स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेजों के चल रहे वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य गैर-हस्तांतरित या गैर-स्थानीय पंजीकरणों के दुरुपयोग को रोकना है।

पुलिस ने बताया कि यह अभियान घाटी के कई जिलों में चलाया गया। टीमों को तैनात किया गया था ताकि बिक्री के बाद नए मालिक के नाम पर हस्तांतरित न किए गए वाहनों के साथ-साथ उचित दस्तावेजों के बिना चल रहे दूसरे राज्य के पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान और उन्हें जब्त किया जा सके। जिलों में कई चौकियों पर पुलिस टीमों ने वाहनों के उचित दस्तावेजों और अद्यतन स्वामित्व रिकॉर्ड की जांच की। पुलिस ने बताया कि यह अभियान यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन के अनुचित दस्तावेजों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य वाहन स्वामित्व रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना, गैर-हस्तांतरित या गैर-स्थानीय पंजीकरणों के दुरुपयोग को रोकना और पूरे जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। पुलिस ने बताया कि जांच अभियान के दौरान कई वाहनों को रोका गया और उनकी जांच की गई। जिन वाहनों में अनिवार्य स्वामित्व हस्तांतरण दस्तावेज या वैध कागजात नहीं थे, उन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे वाहन खरीदने के तुरंत बाद अनिवार्य हस्तांतरण औपचारिकताओं को पूरा करें और सभी वैध दस्तावेजों को हमेशा उपलब्ध रखें।

एचआईवी/एड्स पर जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित

कठुआ, 12 दिसंबर (हि.स.)। सरकारी डिग्री कॉलेज मढ़हीन के रेड रिबन क्लब और ईवीएस विभाग ने एचआईवी/एड्स के बारे में छात्रों को शिक्षित करने और जन स्वास्थ्य जागरूकता पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य विषय एड्स का अंत, सशक्त बनाना, शिक्षित करना, कार्य करना था। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. (डॉ.) अनुपमा गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने जीवंत रंगों, रचनात्मक पैटर्न और प्रभावशाली संदेशों का उपयोग करते हुए एचआईवी की रोकथाम, उपचार, करुणा, समावेश और नियमित जांच के महत्व जैसे विषयों को दर्शाया। कई रंगोली डिजाइनों में रेड रिबन के वैश्विक प्रतीक को प्रमुखता से दर्शाया गया, जो एचआईवी से पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में पांच समूहों ने भाग लिया जिनमें से प्रत्येक समूह में तीन छात्र थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान समूह 1 ने, द्वितीय स्थान समूह 2 ने और तृतीय स्थान समूह 4 ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का कुशल समन्वय रेड रिबन क्लब के संयोजक डॉ. बलविंदर सिंह ने किया। कार्यक्रम का निर्णायक प्रोफेसर संदीप चैधरी, डॉ. मुनीशा देवी और डॉ. शालू रानी ने किया।

संपादकीय

जम्मू में और गहराती ट्रैफिक समस्या

यह एक आम कहावत है कि लोगों को पुराने समय से सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जम्मू में बैठे लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें जम्मू शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल के भविष्य की कोई परवाह नहीं है।

जम्मू की जो पीढ़ी आज भी 1980 और 1990 के दशक की बातें याद करती है, उसे कच्ची छावनी में सालों से खराब पड़े ट्रैफिक लाइट सिग्नल के बचे हुए हिस्से भी याद होंगे। उन दिनों लोग सपना देखते थे कि जम्मू में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को रोकने और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए फिर से अच्छी ट्रैफिक लाइटें लगेंगी।

2012 में, जम्मू को फिर से गाड़ियों के ट्रैफिक को चलाने के लिए नए ट्रैफिक सिग्नल मिले, इस उम्मीद के साथ कि लाखों गाड़ियों का ट्रैफिक ठीक हो जाएगा क्योंकि 2.50 करोड़ रुपये के इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत शहर के ज़रूरी चौराहों पर 10 ट्रैफिक सिग्नल के साथ हुई थी, इस वादे के साथ कि जल्द ही धीरे-धीरे ऐसे और सिग्नल लगाए जाएंगे। समय के साथ, पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए और लगभग सभी चौराहों पर लाल, हरी और पीली लाइटें इस तरह से जलती रहती थीं कि ट्रैफिक में कोई अफरा-तफरी न हो।

इस बदलाव के बाद, जम्मू में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एक और टेक्नोलॉजिकल सफलता देखी गई, जिसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का वादा किया गया था। चूंकि इन सभी कामों के लिए करोड़ों रुपये और बड़े पैमाने पर रिसोर्स की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो चीजें मौजूद हैं, उनसे शहर बदकिस्मती से वहीं पहुंच गया है जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि इनमें से कई तथाकथित इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बेकार हो गए हैं, जिससे आने-जाने वालों को बिना किसी परेशानी के रास्ता दिखाने या किसी भी उल्लंघन को रिकॉर्ड करने में मदद नहीं मिल रही है, जिसके लिए अधिकारियों ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं।

ऐसी खराब हालत में, जो लोग इन लाइटों के खराब होने पर पूरा भरोसा रखते हैं, उन्हें क्रॉसिंग पर हरे, लाल या पीले सिग्नल की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वे ट्रैफिक सिग्नल को जंप करने के लिए सही समय ढूंढना पसंद करते हैं, जबकि वे टेढ़े-मेढ़े तरीके से गाड़ी चलाते हैं, ताकि ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बिना समय और सिग्नल का पालन न करने के जोखिम से बच सकें।

इस मुश्किल को और भी चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि इन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई सही मेंटेनेंस पॉलिसी या जवाबदेही का सिस्टम नहीं है। एक बार बड़े तामझाम के साथ लगने के बाद, उनके रेगुलर मेंटेनेंस को पक्का करने की ज़िम्मेदारी हवा में उड़ जाती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर समय से पहले ही खराब हो जाता है। चाहे यह खराब प्लानिंग, टेक्निकल जानकारी की कमी, या पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही के कारण हो, नतीजा एक ही है- जनता का पैसा बर्बाद होता है, और नागरिकों को इसके नतीजों से निपटना पड़ता है। पिछली गलतियों से सीखने के बजाय, अधिकारी वही गलतियाँ दोहराने के चक्कर में फंसे हुए दिखते हैं, जिससे जनता का भरोसा कम होता है और जम्मू की सड़कों पर बढ़ती अव्यवस्था में योगदान होता है।

यह सच में अजीब है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस ज़रूरी मुद्दे को दिखाने के बावजूद, संबंधित अधिकारी गहरी नींद में हैं या जानबूझकर इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, जैसे उनका मकसद सिर्फ़ ये सिस्टम लगाना और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली पार्टियों को इनाम देना था, और कुछ नहीं।

संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास - नए अधिनियम से क्या हासिल होगा

- डा. रतन कुमार सिन्हा

मामले में, इस संस्कृति को एक संस्थागत फ्रेमवर्क के ज़रिए मज़बूत किया जाना चाहिए। दायित्व - स्पष्टता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) एक अग्रणी कदम रहा है जिसने तीन महत्वपूर्ण हितों को संतुलित किया है- जनता की संरक्षा, आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन और ऑपरेटरों का विश्वास। इसने दोष-रहित दायित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी स्पष्ट और निर्देशित रहे। ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने संबंधित संस्थाओं की देनदारियों पर अधिक स्पष्टता को आवश्यक बना दिया है।

जनता का विश्वास हमेशा से भारत के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रहा है। देश के सतत, समतापूर्ण और ऊर्जा-सुरक्षित विकास के दृष्टिकोण में यह आधार निहित है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक संरक्षा, निर्विवाद उत्तरदायित्व और पारदर्शी संचार के साथ किया जाए। संरक्षा, दायित्व और जन विश्वास के स्तंभ केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं; ये भारत के परमाणु उद्योग के व्यावहारिक आधार हैं। जैसे-जैसे हम परमाणु ऊर्जा के लिए एक नए विधायी ढाँचे पर विचार कर रहे हैं, यह पूछना ज़रूरी है कि यह नए अधिनियम से क्या हासिल होगा मेरे विचार से, इसका उत्तर इन्हीं आधारों को मज़बूत करने में निहित है। इस कानून से अपेक्षा है कि यह जनता के विश्वास से समझौता किए बिना संरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करे, सरलीकरण और सुरक्षा प्रदान करे, नवाचार को प्रोत्साहित करे।

संरक्षा - पूर्णता की संस्कृति को संस्थागत बनाना परमाणु प्रौद्योगिकी में संरक्षा डिज़ाइन का एक अनिवार्य अंग ही नहीं, बल्कि यह इसका मूल दर्शन होना चाहिए। ट्रॉम्बे में भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टरों से लेकर स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टरों और अगली पीढ़ी के प्रगत रिएक्टरों तक, डिज़ाइन हमेशा गहन संरक्षा और निश्चेष्ट संरक्षा विशेषताओं द्वारा निर्देशित रही हैं।

जब हमने प्रगत भारी पानी रिएक्टर की कल्पना की थी, तो हमारा लक्ष्य न केवल थोरियम के उपयोग को प्रदर्शित करना था, बल्कि यह भी प्रदर्शित करना था कि एक रिएक्टर इसके ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना भी सुरक्षित रह सकता है - एक ऐसी डिजाइन जो स्वत- सुरक्षित हो। वास्तव में, संरक्षा परमाणु ऊर्जा परिनियोजन का एक अभिन्न अंग है। नए अधिनियम को, निश्चित रूप से, यह गारंटी देनी चाहिए कि संरक्षा-संस्कृति जारी रहे। इसे उच्चतम संरक्षा मानकों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और नियामक संस्थानों की स्वायत्तता, अधिकार और जवाबदेही को मजबूत करना चाहिए। इसे आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी उन्नयन और पारदर्शी संरक्षा समीक्षाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे प्रचालन प्रदर्शन पर सूचना के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी उद्योग में विशेषकर परमाणु ऊर्जा के मामले में तो और भी ज्यादा, संरक्षा एक स्थिर लक्ष्य नहीं है। इसे एक ऐसी संस्कृति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसका निरंतर पोषण किया जाना चाहिए।

ख़ास तौर पर परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में, इस संस्कृति को एक संस्थागत फ्रेमवर्क के ज़रिए मज़बूत किया जाना चाहिए। दायित्व - स्पष्टता के साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम (सीएलएनडी अधिनियम) एक अग्रणी कदम रहा है जिसने तीन महत्वपूर्ण हितों को संतुलित किया है- जनता की संरक्षा, आपूर्तिकर्ताओं को आश्वासन और ऑपरेटरों का विश्वास। इसने दोष-रहित दायित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह सुनिश्चित किया कि ऑपरेटर की जम्मिदारी स्पष्ट और निर्देशित रहे। ऊर्जा परिदृश्य और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास ने संबंधित संस्थाओं की देनदारियों पर अधिक स्पष्टता को आवश्यक बना दिया है।

इस तरह के संशोधन किसी भी परिपक्व क्षेत्र की स्वाभाविक प्रगति का हिस्सा हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन का फ्रेमवर्क वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखे। नए अधिनियम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन का फ्रेमवर्क निष्पक्ष, स्पष्ट हो और संदेह रहित बना रहे, साथ ही जवाबदेही की एक सुपरिभाषित श्रृंखला भी बनाए रखे। इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दायित्व का मूल्यांकन करने की व्यवस्था देश में परमाणु तैनाती की सीमा और पैमाने के अनुरूप हो। एक आधुनिक दायित्व व्यवस्था को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि संरक्षा और ज़िम्मेदारी विकास के साथ-साथ चलती हैं। जन विश्वास - प्रगति की आधारशिला दुनिया भर में परमाणु उद्योग के उत्कृष्ट संरक्षा रिकॉर्ड के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के प्रति जनता का दृष्टिकोण अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में धारणाओं से अधिक प्रभावित होता रहा है। कुछ साल पहले मैंने जिस पुस्तक का सह-लेखन किया था, अनरीज़न्ड फियर ऑफ़ रेडिएशन ऐसी ही भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास था। यह पुस्तक बताती है कि नियंत्रित और सुव्यवस्थित वातावरण में विकिरण, किसी भी अन्य तकनीक जितना ही सुरक्षित है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से आत्मविश्वास से करते हैं। जनता का विश्वास केवल पारदर्शिता और जनता के साथ संवाद के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब नागरिक देखते हैं कि परमाणु विज्ञान रेडियोथेरेपी के माध्यम से जीवन बचा रहा है, उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से फसलों को बढ़ा रहा है या विकिरण शुद्धिकरण के माध्यम से सुरक्षित जल उपलब्ध करा रहा है, तो वे परमाणु ऊर्जा के मानवीय पहलू से जुड़ने लगते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, हमने नई आउटरीच रणनीतियों की शुरुआत करके इस दिशा में कई प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में परमाणु ऊर्जा विभाग की झांकी प्रदर्शित की गई और प्रसारण व सोशल मीडिया पर उपस्थिति दर्ज कराई गई। ये कदम दिखावटी नहीं थे; इनका उद्देश्य विज्ञान और समाज के बीच की दीवार को हटाना था। यदि नया अधिनियम नागरिकों के साथ खुले संवाद को बढ़ावा दे पाता है, तो यह समाज के साथ विज्ञान के सामाजिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करेगा। ऐसा करके, यह हमारे चिरस्थायी आदर्श वाक्य- राष्ट्र की सेवा में परमाणु, की भावना को साकार करेगा। नए अधिनियम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के संदेश सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाएं, शैक्षिक जागरूकता को प्रोत्साहित करें तथा नागरिकों के साथ संवाद को संस्थागत कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाएं। नए अधिनियम में क्या गारंटी होनी चाहिए यदि 1962 के प्रथम परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने क्षमता निर्माण के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो नए अधिनियम का उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना और परमाणु प्रौद्योगिकी की बड़े पैमाने पर तैनाती करना होना चाहिए। इसमें उस राष्ट्र की परिपक्वता प्रतिबिंबित होनी चाहिए जिसने जटिल तकनीकों में महारत हासिल की है और जिम्मेदार आचरण के माध्यम से वैश्विक सम्मान अर्जित किया है।

नए अधिनियम को विज्ञान और समाज के बीच पारस्परिक आश्वासन की यह गारंटी देनी चाहिए कि- संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, दायित्व (देनदारियां) हमेशा न्यायसंगत और पारदर्शी रहेगा, और जनता का विश्वास हर निर्णय के केंद्र में रहेगा। जब ये गारंटियां न केवल कानून में, बल्कि संस्थागत व्यवहार में भी निहित होंगी, तो भारत का परमाणु भविष्य सुदृढ़ आधार पर खड़ा होगा। विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह एक परिवर्तन का दौर है। बड़े विद्युत संयंत्रों के अलावा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और प्रगत थोरियम प्रणालियाँ परमाणु ऊर्जा की पहुँच का विस्तार करेंगी। इसलिए नए अधिनियम को एक ऐसे फ्रेमवर्क की गारंटी देनी चाहिए जो प्रौद्योगिकियों के तेज़ उपयोग को सुगम बनाए और साथ ही स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करे। इसमें नियामकों, प्रचालकों और उद्योग के बीच निर्बाध समन्वय और भविष्य के नवाचारों को शामिल करने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना चाहिए। संक्षेप में, नए अधिनियम को परमाणु पुनर्जागरण के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए जो भारत में जलवायु लक्ष्यों और विकसित भारत @2047 बनने की राह में स्वच्छ-ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विश्व का अग्रणी देश बनने की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

पूर्व सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
एवं पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग

स्वास्थ्य के अधिकार की लड़ाई

- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा और उसकी दिशा तेजी से बदल रही है। चिकित्सा, जो कभी सार्वजनिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी माना जाता था, अब अधिकाधिक निजी क्षेत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। एक ओर, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सीमित बजट, कम मानव संसाधन और कमजोर बुनियादी ढांचे से जूझ रहा है; दूसरी ओर, निजी अस्पतालों और कॉरपोरेट मेडिकल चेन की पहुंच और उसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों के बीच आम नागरिक, विशेषकर गरीब-ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और असमान पहुंच के बोझ तले दब रहे हैं।

इसी बदलते परिदृश्य में, यह बहस तेज हो गई है कि क्या स्वास्थ्य को न्यायसंगत और लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बनाया जा सकेगा। यह कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्न भी है।

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर इसे अभी तक स्पष्ट रूप से स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें हर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, परंतु स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक व्यय आज भी दुनिया के सबसे कम आंकड़ों में शामिल है। जब राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट नहीं देता, तब स्वाभाविक रूप से रिक्त स्थान निजी क्षेत्र भरता है और यहीं से उत्पन्न होती है अनियंत्रित शुल्क, अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाएँ और आम व्यक्ति की आर्थिक तबाही।

निजीकरण के विस्तार का दूसरा पहलू यह है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन तक सीमित नहीं है; यह स्वास्थ्य नीति, दवाओं की कीमतों, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। जब स्वास्थ्य एक लाभ आधारित उद्योग में बदल जाता है तब उपचार की प्रकृति, लागत, पहुंच और गुणवत्ता सभी बाज़ार के नियमों के अधीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो हो सकता है पर धरातल पर वह व्यापक रूप से लागू नहीं हो पाता।

एक और गंभीर समस्या है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 का कमजोर क्रियान्वयन। जिन राज्यों में यह लागू भी है, वहाँ भी नियमन और पारदर्शिता कमजोर हैं। मरीज़ों से मनमाना शुल्क, अनावश्यक जाँच की सलाह, महंगे पैकेज और अत्यधिक दरों पर सर्जरी जैसी शिकायतें आम हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मरीज़ की ओर से शिकायत या न्याय पाने की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी हो।

इसके साथ ही, भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी कुल स्वास्थ्य व्यय का 40% के आसपास है। यानी मरीज़ों को अपनी जेब से भारी राशि खर्च करनी पड़ती है। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी बीमा योजनाओं का उद्देश्य भले आर्थिक सुरक्षा देना हो, पर इनके दायरे में आने वाली प्रक्रियाएँ सीमित हैं और निजी अस्पतालों द्वारा इनका उपयोग कई बार मनमाने ढंग से किया जाता है। बीमा आधारित मॉडल ने स्वास्थ्य खर्च की समस्या को हल नहीं किया है बल्कि कई बार यह निजी क्षेत्र के लिए नया ग्राहक-स्रोत बन गया है।

स्वास्थ्य अधिकार को न्यायिक रूप से लागू करना तभी संभव है जब स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कम-से-कम 5% खर्च होना चाहिए; जबकि भारत अभी 2% से भी कम खर्च करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किए बिना, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए बिना, दवाओं और जांचों को सस्ता किए बिना और स्वास्थ्य संस्थानों में जवाबदेही मजबूत किए बिना, इस अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की कोशिशें बेमानी होगी।

दवाओं की ऊँची कीमतें और दवा कंपनियों का प्रभाव, इसमें कोढ़ में खाज जैसी स्थिति पैदा करता है। लगभग 80ब दवाएँ अभी भी मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं। जब तक आवश्यक दवाओं पर सख्त मूल्य नियंत्रण नहीं होगा तथा जन औषधि प्रणाली का विस्तार नहीं होगा, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार महंगी दवाओं के भार तले दबते रहेंगे।

साथ ही, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थितियाँ भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अस्थायी नियुक्तियाँ, कम वेतन, कार्यभार का दबाव- ये सभी कारक चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तभी संभव है जब सरकार मानव संसाधन में उचित निवेश करे।

स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लंबी अवधि का कार्य है; परंतु इसकी शुरुआत तत्काल बजट बढ़ाने, निजी अस्पतालों को सख्त नियामक दायरे में लाने, दवाओं की कीमतें नियंत्रित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने से हो सकती है। यह मजबूत स्वस्थ ढांचा की नींव रखेगा।

यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल आर्थिक विकास का फल नहीं, मानव गरिमा की बुनियाद है। जब तक इस बुनियाद को समान रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, स्वास्थ्य का अधिकार कागज़ पर तो रहेगा पर जनता के जीवन में नहीं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ऊर्जा-संकट से बचने लिए जरूरी है ऊर्जा संरक्षण

गिरीश्वर मिश्र

ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भौतिक नियम बताता है कि ऊर्जा न पैदा की सकती है न समाप्त; उसका सिर्फ़ रूपांतरण ही होता है। मानव जीवन की सारी गतिविधियाँ इस मायावी ऊर्जा पर ही टिकी हुई हैं। ऊर्जा ही अपना रूप बदल-बदल कर हमारी कल्पनाओं को साकार करती है। सामान्यत- अदृश्य-सी रहने वाली ऊर्जा हमारे दृश्य जगत को रचते हुए हर जगह हावी है। ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जाते रहे हैं जो आणविक ऊर्जा तक पहुँचे हैं। ईंधन से भोजन बनाने में ही नहीं उसके लिए प्रयोग में आने वाली सामग्री हम तक पहुचे इसके लिए हर कदम पर जरूरी मशीन, उर्वरक, पानी सबके लिए अलग-अलग तरह से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही परिवहन, मौसम से सुरक्षा और वस्तुओं के निर्माण के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है।

दरअसल, आधुनिक जीवन शैली, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रश्न आपस में बुरी तरह से गुँथे हुए हैं। विकास के साथ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की माँग बढ़ रही है। समृद्ध देशों में जीवन स्तर को उन्नत रखने के लिए अधिकाधिक ऊर्जा चाहिए, उभरते देशों में कृषि अर्थ व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ़ आगे बढ़ने में भी ऊर्जा चाहिए। परंतु यह भी जरूरी है कि उन 80 प्रतिशत लोगों के साथ मिल कर काम किया जाय जिनके पास केवल एक चौथाई संपत्ति है। ऊर्जा की समस्या वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कई जटिल समस्याओं का परस्पर गुँथा समूह है।

भारतवर्ष की विशालकाय जनसंख्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी के कारण यहाँ ऊर्जा की माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व में ऊर्जा की खपत की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। परंतु हमारा बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ रहा है जिसके चलते बिजली आपूर्ति में बड़ी बाधा पहुँचती है और उसका दुरुपयोग भी होता है। साथ ही देश में ऊर्जा की ग़रीबी भी बनी हुई है। दुर्बल वर्ग के लोगों को बिजली और अन्य आधुनिक ऊर्जा के संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। यह भी गौरतलब है कि जीवाश्म ऊर्जा (फॉसिल फ्यूल) के अत्यधिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव है और वह ख़तरनाक साबित हो रहा है।

भारत की ऊर्जा मुख्यतया जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल तथा गैस आदि से उपलब्ध होती है। आज देश में बिजली उत्पादन का 70 प्रतिशत कोयले पर टिका है। आयात और घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते यह अब बड़ा मंहगा पड़ रहा है। इस पर निर्भरता, ऊर्जा की बढ़ती मांग, अन्य देशों पर निर्भरता, पुराने क़िस्म का ढाँचा और नवीकरण की संभावना वाले ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में धीमी गति ने देश के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इनसे ऊर्जा-सुरक्षा, विकास के टिकाऊपन और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं जन्म ले रही हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश तो बढ़ा है फिर भी कच्चे तेल और कोयले के आयात के कारण आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हो और ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाय। देश को अपने संसाधनों की खोज बढ़ानी होगी ताकि ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण के नेटवर्क को अविलंब सुधारना होगा ताकि ऊर्जा चोरी और दुरुपयोग की रोकथाम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समस्या अगले सौ वर्षों में मानवता की शीर्ष दस समस्याओं में से एक गंभीर समस्या बनेगी। वह मानवता के सम्मुख खड़ी समस्याओं में विकटतम हो रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले खाड़ी युद्धों और सद्य- चल रहे युद्ध की पृष्ठभूमि में ऊर्जा का प्रश्न भी मौजूद है। बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा की ज़रूरतें निरंतर बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा समस्या से निपटने की एक अच्छी युक्ति है। सौर ऊर्जा मानव जाति की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भी है। इस विशाल ऊर्जा स्रोत का दोहन एक समाधान है। ऊर्जा संरक्षण के प्रश्न पर विचार करते हुए कम खर्चीले और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोतों की खोज जारी है। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में प्रगति हुई है।

ऊर्जा संकट का एक व्यवहारिक पक्ष भी है। इस संकट का समाधान ऊर्जा-संरक्षण के लिए जरूरी अभ्यास की अपेक्षा करता है। आदतों में बदलाव द्वारा ऊर्जा के उपभोग में कमी लाकर ऊर्जा के दुरुपयोग को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। इस दृष्टि से विभिन्न कार्यों के लिए कम ऊर्जा की खपत वाली ऊर्जा-सक्षम तकनीकों का अवलंबन भी कारगार साबित होगा। ऐसे कदम उठाने का पर्यावरणीय लाभ भी मिलेगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन पर नियंत्रण होगा और दूसरे प्रदूषकों, जो जलवायु-परिवर्तन को तीव्र करते हैं और प्राकृतिक आवास का क्षरण करते हैं उनसे रक्षा भी होगी। इससे घर या व्यापार हर क्षेत्र में खर्चे में कमी आएगी। ऊर्जा संरक्षण के लिए संसाधन-प्रबंधन की सख़्त ज़रूरत है। हमें वर्तमान ऊर्जा-संसाधनों का विस्तार करना होगा और ऊर्जा-सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इन सब उपायों से आयातित ऊर्जा पर हमारी निर्भरता घट सकेगी।

वस्तुत- ऊर्जा-संरक्षण का लक्ष्य अपने व्यवहार-बर्ताव में बदलाव तथा विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी के विकास द्वारा पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर में बिजली का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। कमरे से बाहर जाते समय ध्यान से स्विच ऑफ़ कर देने की आदत बिजली बिल में बड़ी बचत ला सकता है। प्राकृतिक प्रकाश का अधिकाधिक उपयोग करना भी प्रभावी उपाय है। ऊर्जा की किफायत वाले एलएडी बल्ब लगाने से लगभग 75 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है। इसी तरह विभिन्न उपकरणों के उपयोग के तरीकों को भी सुधारना होगा। जब उपकरण को उपयोग में न ला रहे हों तो अनप्लग कर देना, स्वचालित ऑफ़ होने की व्यवस्था रखना बहुत लाभकर होता है। हीटिंग और कूलिंग के लिए प्रोग्राम वाली थर्मोस्टेट की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। आज यातायात में भी ऊर्जा की बड़ी खपत होती है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि कम से कम ड्राइव करें। इसकी जगह पैदल चलना, साइकिल का उपयोग, परिवहन के जन-माध्यम (जैसे- बस, ट्रेन, मेट्रो आदि) का उपयोग बड़ी कारगार पहल हो सकती है। निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सड़कों पर वाहनों की अतिरिक्त भीड़ जिससे जाम लगता है और प्रदूषण होता है घटेगी। वाहन को अनावश्यक तेज या कम गति से नहीं चलाना चाहिए। इसी दृष्टि से हाइब्रिड, बिजली का वाहन या वह जो कम ईंधन की खपत करता हो आ रहे हैं और लोकप्रिय भी हो रहे हैं।

व्यापार-व्यवसाय का नियमित ऊर्जा आडिट किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा के दुरुपयोग का ठीक से पता चल सके और ऊर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग सुझाया जा सके। उपकरणों को अपग्रेड करना तथा ऐसी प्रणाली लागू करना जो अपशिष्ट औद्योगिक ऊर्जा का उपयोग कर सके लाभकर सिद्ध होगा। आज जान बूझकर ऊर्जा का कम-से-कम उपयोग करने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि खर्च में कमी हो, अपशिष्ट कम पैदा हो, पर्यावरण की रक्षा हो और भविष्य के लिए ऊर्जा-सुरक्षा भी हो सके। कम-से-कम ऊर्जा सेवाओं का लाभ लेना और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हरित अभियांत्रिकी के तौर-तरीके अपनाने होंगे।

ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग एक बहुआयामी प्रश्न है जिसके साथ राजनैतिक मुद्दे, तकनीकी विकास, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण के सरोकार महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उपभोक्ता व्यवहार जटिल होता है और व्यक्तित्व, सामाजिक मानक, ऊर्जा-संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति, आरामदायक जीवन शैली की पसंद, ऊर्जा-सुरक्षा की चेतना, पर्यावरण के प्रति मैत्री आदि पर निर्भर करता है। ऊर्जाक्षम प्रणालियों को अपनाने और विवेकपूर्ण ऊर्जा का उपयोग द्वारा ही ऊर्जा संरक्षण संभव है। उपभोक्ता व्यवहार को बदल कर ही दीर्घकालिक और स्थायी समाधान मिल सकेगा। विवाह समारोह, संगीत, नृत्य, रैली और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम बताते हैं कि हमारी बिगड़ी आदतें ऊर्जा की माँग को बढ़ाती जा रही हैं अनावश्यक ऊर्जा उपयोग किसी के हित में नहीं है। ऊर्जा की समस्या सार्वभौमिक है और जैसा स्टॉकहोम घोषणा में कहा गया था पृथ्वी एक है, इस बात को साबित कर रही है। ऊर्जा के मुद्दे आधुनिक समाज में ऊर्जा के वितरण, उपलब्धता और आपूर्ति के साथ उसके टिकाऊपन और स्वच्छ यानी प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत की तलाश तकनीकी उन्नति के साथ ही हमारे संस्कार और व्यवहार पर भी निर्भर करेगा।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

विनेश फोगाट का बड़ा ऐलान : संन्यास वापस लिया, 2028 ओलंपिक में उतरने का किया ऐलान

एजेंसी

चंडीगढ़। भारतीय महिला पहलवानी की स्टार विनेश फोगाट ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। कुछ महीनों पहले पहलवानी से दूरी बनाने और राजनीति में कदम रखने वाली विनेश अब दोबारा मैट पर लौटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनका सफर खत्म नहीं हुआ है–अब उनकी नजर लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक पर है। सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए विनेश ने लिखा कि पेरिस ओलंपिक के बाद लोग लगातार पूछ रहे थे–क्या यही उनका आखिरी मुकाबला था विनेश ने माना कि उन्हें लंबे समय तक इस सवाल का जवाब नहीं पता था। पेरिस के बाद उन्हें अपने खेल, दबाव, उम्मीदों और यहां तक कि अपने सपनों से भी कुछ समय की दूरी चाहिए थी। इसी दौरान उन्होंने समझा कि वह अब भी खेल से उतना ही प्यार करती हैं और प्रतिस्पर्धा करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय के सन्नाटे ने उन्हें एहसास दिलाया कि उनके भीतर की आग कभी बुझी नहीं थी–बस थकान और शोर में छिप गई थी। अनुशासन, लड़ाई और मैट पर खड़े होने की चाह अब भी उनके भीतर जिंदा है। विनेश ने आगे लिखा कि वह अब नए जोश और निडर दिल के साथ LA28 की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इस बार उनकी यात्रा और भी खास होगी, क्योंकि उनका बेटा भी उनके साथ रहेगा–उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और उनका छोटा सा चीयरलीडर।

जूनियर हॉकी महिला विश्व कप: स्पेन से हारकर 10वें स्थान पर रही भारतीय टीम

सैंटियागो । भारतीय महिला हॉकी टीम को जूनियर हॉकी विश्व कप में स्पेन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली कुल टीमों की सूची में 10वें स्थान पर रही। भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम की तरफ से एकमात्र गोल कनिका सिवाच (41') ने किया। वहीं स्पेन की तरफ से नतालिया विलानोवा (16') और एस्थर कैनालेस (36') ने गोल किया। पहला क्वार्टर बहुत रोमांचक रहा। दोनों टीमों की तरफ से गोल के प्रयास किए गए, लेकिन दोनों ही टीमें गोल करने में असफल रहीं। 14वें मिनट में, स्पेन को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे निधि ने रोक दिया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में स्पेन ने आक्रामक खेल की शुरुआत की। सारा कार्मोना रामोस ने सर्कल के चारों ओर कुशलता से ड्रिबल किया और अंदर एक पास दिया, जिसे नतालिया विलानोवा (16') ने सफलतापूर्वक गोल में बदल टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अगले कुछ मिनटों में भारत को कुछ मौके मिले, लेकिन टीम इंडिया उन मौकों को गोल में बदल पाने में सफल नहीं हो सकी।

न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर 9 विकेट से जीत, डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में तीसरे नंबर पर पहुंचे कीवी

नई दिल्ली । न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ पर नौ विकेट से बड़ी जीत हासिल करके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इस जीत से न्यूजीलैंड को 12 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स मिले और अब कीवी टीम स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर आ गई है। इस जीत के साथ ही 2021 की चैंपियन टीम न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और भारत को पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड का अब जीत-हार का प्रतिशत 66.67 है, जबकि टॉप पर चल रही ऑस्ट्रेलिया (100 प्रतिशत) और दूसरे स्थान पर चल रही साउथ अफ्रीका (75 प्रतिशत) ही उनसे आगे हैं। मैच की बात करें तो वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस जीत में जैकब डफी की शानदार गेंदबाजी ने अहम योगदान दिया, जिन्होंने इस मैच में पांच विकेट लेकर सीरीज में दूसरा फाइव-विकेट हॉल पूरा किया।

मूनी की तूफानी पारी, सिक्सर्स के खिलाफ जीत के साथ फाइनल में स्कॉर्चर्स

सिडनी। पर्थ स्कॉर्चर्स ने विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के चैलेंजर्स मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 11 रन से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। अब यह टीम शनिवार को फाइनल में होबार्ट हेरिकेंस से भिड़ेगी। नॉर्थ सिडनी ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 183 रन बनाए। इस टीम के लिए केटी मैक और बेथ मूनी ने 7.2 ओवरों में 66 रन की साझेदारी की। मैक 30 गेंदों में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटीं। यहां से बेथ मूनी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने महज 44 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के के साथ 76 रन की पारी खेलते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इनके अलावा, पेज स्कोफील्ड ने 14 रन, जबकि अलाना किंग ने 11 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी टीम की ओर से कप्तान एश्ले गार्डनर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि मैतलान ब्राउन और अमेलिया केर ने 2-2 विकेट निकाले। लॉरेन चीटल ने एक विकेट हासिल किया। इसके जवाब में सिडनी सिक्सर्स की टीम 20 ओवरों के खेल तक 6 विकेट खोकर सिर्फ 172 रन ही बना सकी। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। सोफी डंकले ने एलिस पेरी के साथ 7.3 ओवरों में 58 रन की साझेदारी की। एलिस 22 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सोफी ने 30 गेंदों में 41 रन टीम के खाते में जोड़े। टीम 74 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी।

अर्शदीप सिंह ने 7 वाइड गेंदें डालकर टी20आई इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया, पहले इस खिलाड़ी के नाम था

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टी20आई में वह देखने को मिला जिसकी किसी भारतीय क्रिकेट फैन ने उम्मीद नहीं की थी। अपने घरेलू मैदान मुल्लांपुर में खेलते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए सबसे महंगी ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने एक ओवर में 7 वाइड फेंकीं और कुल 13 गेंदें डालीं, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भारतीय की ओर से अब तक की सबसे खराब लय का रिकॉर्ड है। इस प्रदर्शन ने न केवल टीम को मुश्किल में डाला बल्कि फैंस को भी निराश कर दिया।

होम ग्राउंड पर अर्शदीप का निराशाजनक प्रदर्शन

महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में दर्शकों की नज़रें अपने स्थानीय स्टार अर्शदीप सिंह पर टिकी

थीं। लेकिन मैदान पर उनकी गेंदबाजी बिल्कुल उलटी दिशा में गई। टीम इंडिया इस मैच में बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद के साथ उतरी थी, पर अर्शदीप ने शुरुआती दो ओवरों में 20 रन दे दिए। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ड्रिंक्स ब्रेक के बाद उन्हें गेंद थमाई, जहाँ मामला और खराब हो गया।

टी20आई इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड

अर्शदीप ने मैच के 11वें ओवर में कुल 13 गेंदें डालीं। इसमें शामिल थीं:

7 वाइड गेंदें

6 लीगल डिलिवरी

ओवर में कुल 18 रन

इस ओवर में एक छक्का, तीन सिंगल, एक डबल और वाइड से आए सात रन शामिल थे। यह भारत की ओर से टी20ढ्ढ क्रिकेट में सबसे लंबा ओवर है। इससे पहले किसी भारतीय गेंदबाज ने एक ओवर में इतनी गलत गेंदबाजी नहीं की थी।

दुनिया के दूसरे गेंदबाज जिसने 13 गेंदों का ओवर डाला : अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 13 गेंदों का ओवर फेंकने वाले वे दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।इससे पहले अफगानिस्तान के नवीन-उल-हक ने पिछले साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों का ओवर फेंका था, जिसमें 6 वाइड और एक नो-बॉल शामिल थी।

फुल मेंबर नेशन में सबसे बड़ा ओवर : दक्षिण अफ्रीका के सिसांडा मागला ने पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 12 गेंदों का ओवर फेंका था। अर्शदीप ने यह रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया और नवीन-उल-हक की बराबरी कर ली।

सूर्यकुमार ने दूसरे टी20आई में हार की जिम्मेदारी ली, कहा- हर बार अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते

एजेंसी

मुल्लांपुर : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि टीम अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकती मुझे, शुभमन गिल और अन्य को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत को मिली 51 रनों से हार के बाद सूर्यकुमार ने कहा, 'मेरा मानना है कि मुझे और शुभमन को अच्छी शुरुआत देनी चाहिए थी, क्योंकि हम हर बार अभिषेक पर निर्भर नहीं रह सकते। वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका भी खराब दिन हो सकता है इसलिए मुझे, शुभमन को और कुछ अन्य बल्लेबाजी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। शुभमन पहली ही गेंद पर आउट हो गए। मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और थोड़ी देर तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी।'

सूर्यकुमार ने अक्षर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर कहा , 'हमने पिछले मैच में सोचा था कि अक्षर ने लंबे प्रारुप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और हम चाहते थे कि वह आज भी उसी तरह बल्लेबाजी करे। लेकिन दुर्भाग्य से (वह काम नहीं आया), हालांकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की।' उन्होंने कहा, 'हमने पहले गेंदबाजी की, तो हमें अच्छी वापसी करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजो को एहसास हुआ कि इस विकेट पर लेंथ कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सीखने की प्रक्रिया है। बस सीखो और आगे बढ़ो। थोड़ी ओस भी थी, और अगर हमारा प्लान काम नहीं कर रहा था, तो हमें दूसरा प्लान तैयार रखना चाहिए था। हमने देखा कि उन्होंने दूसरी पारी में कैसे गेंदबाजी की। हमने उनसे सीखा, और हम अगले मैच में उसे लागू करने की कोशिश करेंगे।'

बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सिंधू-लक्ष्य सहित इन खिलाड़ियों को मौका

एजेंसी

नई दिल्ली : दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू, लक्ष्य सेन और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी को तीन से आठ फरवरी तक चीन के किंगदाओ में होने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारत इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में गत चैंपियन है जबकि पुरुष टीम ने अतीत में दो कांस्य पदक जीते हैं।

भारतीय बैडमिंटन संघ ने एक बयान में कहा, 'रैंकिंग, प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर चुनी गई महिला टीम की अगुवाई एक बार फिर पूर्व विश्व चैंपियन और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू करेंगी।' दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य शीर्ष रैंकिंग वाले पुरुष एकल खिलाड़ी होंगे जबकि किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, अमेरिकी ओपन विजेता आयुष शेट्टी और तरुण मन्नेपल्ली को भी जगह मिली है। सात्विक-चिराग पुरुष युगल वर्ग में अगुवाई करेंगे जिसमें गुवाहाटी मास्टर्स के उप विजेता साई प्रतीक के और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय के साथ

हरिहरन अमसाकरुणन भी शामिल हैं। महिला वर्ग में सिंधू को एकल में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, रक्षिता श्री संतोष रामराज और मालविका बंसोड़ का साथ मिलेगा। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियन गायत्री गोपीचंद और त्रीसा जॉली महिला युगल में भारत की अगुवाई करेंगी जबकि प्रिया कोंजेंगबम, श्रुति मिश्रा और तनीषा क्रास्टो को भी टीम में जगह मिली है।

टीमें :

पुरुष : लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, प्रणय एचएस, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय, साई प्रतीक के, हरिहरन अमसाकरुणन।

महिला : पीवी सिंधू, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री संतोष रामराज, मालविका बंसोड़, त्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद, प्रिया कोंजेंगबम, श्रुति मिश्रा, तनीषा क्रास्टो।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की बिक्री शुरू, शुरूआती कीमत 100 रुपए

एजेंसी

नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट बिक्री के लिए जारी कर दिए हैं जिनकी कीमत पहले फेज में कुछ जगहों के लिए भारत में सिर्फ 100 और श्रीलंका में LKR 1000 से शुरू हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में मिलकर आयोजित किया जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 आठ जगहों पर खेला जाएगा जिसमें भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता होस्ट करेंगे जबकि श्रीलंका में कोलंबो (दो जगह) और कैंडी को चुना गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि BCCI और PCB के बीच हुए एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।

भारतीय जगहों में से सिर्फ कोलकाता और अहमदाबाद में टिकट की कीमतें 100 रुपए से शुरू हो रही हैं। चेन्नई में टिकट की कीमतें 300 रुपए से शुरू हैं, जबकि दिल्ली में यह 150 रुपए से शुरू होती हैं। मुंबई

में टिकट की कीमतें 250 रुपए से शुरू होती हैं। श्रीलंका में टिकट की कीमतें LKR 1000 से शुरू होती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रुप स्टेज मैचों और सुपर 8 स्टेज के टिकट पहले फेज में बिक्री के लिए रखे गए हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट कहां से खरीदें?

Bookmyshow T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकटिंग पार्टनर है जहां से टिकट खरीद सकते हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट कैसे बुक करें?

लॉग इन/रजिस्टर करें मैच/जगह चुनें अपना खास मैच चुनें (भारत बनाम USA) सीटें, कैटेगरी और टिकटों की संख्या चुनें कार्ड, PI, नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा करें बुकिंग की डिटेल्स के साथ एक कन्फर्मेशन ईमेल और SMS आपको मिल जाएगा।

तिलक वर्मा की फिफ्टी गई बेकार, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टी20 में 51 रनों से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

एजेंसी

मुल्लांपुर : क्विंटन डी कॉक (90) अर्द्धशतकीय और डॉनोवन फरेरा (30) की आखिरी ओवरों में विस्फोटक पारी के बाद ऑटनील बाटमैन (चार विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी-20 मुकाबले में भारत को 51 रनों से हरा कर पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में शुभमन गिल (शून्य) का विकेट गंवा दिया। अगले ही ओवर में माकर यानसन ने अभिषेक शर्मा (17) को आउटकर भारत को दूसरा झटका दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (पांच) भी को यानसन ने अपना शिकार बनाया। भारत का चौथा विकेट अक्षर पटेल (21) के रूप में गिरा। इसके बाद करने आये हार्दिक पंड्या ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े। 15वें ओवर लुथो सिपामला ने हार्दिक पंड्या (20) को आउटकर इस साझेदारी

का अंत किया। जितेश शर्मा 17 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली। उन्होंने इसी पारी में दो चौके और दो छक्के भी लगाये। 19वें ओवर में बाटमैन ने शिवम दुबे (एक) और उसके बाद अर्शदीप सिंह (चार) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बाटमैन ने अपना चौथा शिकार वरुण चक्रवर्ती को बना लिया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर लुंगी एन्गिडी ने तिलक वर्मा को आउट भारत की पारी का 163 के स्कोर पर अंत कर दिया। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में पांच छक्के और दो चौके लगाते हुए 62 रनों की पारी। भारत ने अपने आखिरी पांच विकेट मात्र पांच रन जोड़कर गंवा दिये। दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑटनील बाटमैन ने चार विकेट लिये। लुंगी एन्गिडी, माकर यानसन और लुथो सिपामला को दो-दो विकेट मिले।

इससे पहले यहां दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स की जोड़ी ने पहले विकेट लिए 38 रन जोड़े। पांचवें ओवर में वरूण चक्रवर्ती ने रीजा हेंड्रिक्स (आठ) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान एडन मारक्रम ने क्विंटन डी कॉक के साथ 83 रनों की साझेदारी की।

हार के बाद रियल मैड्रिड के खिलाड़ी हुए बेकाबू, कई प्लेयर्स पर लगे प्रतिबंध

एजेंसी

मैड्रिड : सेल्टा विगो से हार के बाद रियल मैड्रिड पर मुख्य रूप से रेफरी के साथ दुर्व्यवहार के कारण उसके खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए गए है। रियल मैड्रिड को सेल्टा विगो के साथ मैच के दौरान दूसरे हाफ में डिफेंडर फ्रान गार्सिया और अल्वारो कैरेरास और फॉरवर्ड एंड्रिक को दिखाए गए रेड कार्ड के लिए भारी अनुशासनात्मक कीमत चुकानी पड़ी। गार्सिया पर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन (RFEF) की अनुशासनात्मक कमेटी ने एक

मैच का बैन लगाया है, जिसे वह इस वीकेंड डेपोर्टिवो अलावेस के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकेंगे। उन्हें दो येलो कार्ड मिलने के बाद मैच से बाहर कर दिया गया था। हालांकि, कैरेरास और एंड्रिक को दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, कैरेरास को रेफरी क्विंटरो गोंजालेज को बाहर किए जाने के बाद 'एरेस मालिसिमो' (तुम बहुत बुरे हो) कहने के लिए सजा दी गई है। मैदान पर नहीं उतरने वाले एंड्रिक को भी रेड कार्ड दिखाया गया और 'बेंच से उठकर टेक्निकल एरिया से बाहर जाने, चौथे रेफरी पर चिल्लाने और टेक्निकल स्टाफ के सदस्यों द्वारा रोके जाने की जरूरत पड़ने' के लिए दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया। घुटने की सर्जरी के बाद फिलहाल बाहर चल रहे डैनी कार्वाजल को भी मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के टनल में रेफरी का अपमान करने के लिए दो मैचों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

BCCI की बैठक में पांच एजेंडों पर होगी चर्चा, महिला क्रिकेटरों की मैच फीस पर भी होगी बात

एजेंसी

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया (एसएलआई) का आयोजन 16 से 26 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। यह घोषणा पहले किए गए उस ऐलान के बाद हुई है, जिसमें लीग के उद्घाटन सत्र को वर्ष 2026 की शुरुआत में कराने की जानकारी दी गई थी। अब अंतिम तारीखें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) के 2026 कैलेंडर के अनुरूप तय की गई हैं, ताकि किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट से टकराव न हो।

इस लीग में देश और विदेश के कई शीर्ष निशानेबाज भाग लेंगे, जिससे दर्शकों को रोमांचक और उच्च स्तरीय मुकाबले देखने को मिलेंगे। शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का उद्देश्य लीग-फॉर्मेट में विश्वस्तरीय शूटिंग को प्रस्तुत करना और खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाना है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कालिकेश नारायण सिंह देव ने एक आधिकारिक बयान में कहा, शूटिंग लीग ऑफ इंडिया हमारे खेल के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह फ्रेंचाइजी आधारित, खिलाड़ी-केंद्रित और वैश्विक कैलेंडर के अनुरूप है, जिससे अधिकतम अंतरराष्ट्रीय भागीदारी संभव होगी। मिश्रित टीम मुकाबलों और प्रीमियम प्रसारण के साथ हम विश्वस्तरीय उद्घाटन सत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। एनआरएआई के महासचिव पवनकुमार सिंह ने कहा, हमें खुशी है कि शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का पहला संस्करण अगले साल की शुरुआत में होगा। इसमें भारत और विदेश के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिससे मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी होंगे। यह लीग शूटिंग खेल को बढ़ावा देने और घरेलू खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर के एथलीटों के साथ खेलने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगी। पूर्व विश्व चैंपियन और शूटिंग दिग्गज रंजन सोढ़ी ने कहा, कसा हुआ प्रारूप, मिश्रित टीम प्रणाली और उम्दा प्रसारण शूटिंग जैसे तकनीकी खेल को भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक बना सकते हैं। यह मंच खेल की बारीकियों को रोचक कहानी में बदलने की क्षमता रखता है। पूर्व विश्व नंबर-1, खेल रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंजलि भगवत ने कहा, यह मंच जूनियर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को वैश्विक सितारों के साथ खेलने और उनसे सीखने का मौका देगा। सुरक्षित कैलेंडर और मजबूत आयोजन व्यवस्था के साथ यह लीग आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सकती है।इस प्रतियोगिता में मिश्रित टीम स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पिस्टल (10 मीटर, 25 मीटर), राइफल (10 मीटर, 50 मीटर थ्री-पोज़िशन) और शॉटगन (ट्रैप व स्कीट) शामिल हैं। फ्रेंचाइजी आधारित टीमों को लीग चरण में दो समूहों में बांटा जाएगा, जिसके बाद नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे।

खिलाड़ियों का ड्राफ्ट चार श्रेणियों – एलीट चैंपियंस, वर्ल्ड एलीट, नेशनल चैंपियंस और जूनियर एवं यूथ में किया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय सितारों, शीर्ष भारतीय निशानेबाजों और उभरती प्रतिभाओं का संतुलित मिश्रण तैयार किया जा सके।

वैभव सूर्यवंशी का यूएई पर तूफानी कहर, अंडर-19 एशिया कप में जड़ा जोरदार शतक

एजेंसी

नई दिल्ली : भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में उन्होंने इसे फिर से साबित कर दिखाया। यूएई के खिलाफ वैभव ने ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया। शुरू में सावधानी से खेलते हुए उन्होंने जैसे ही लय पकड़ी, चौके-छक्कों की बरसात शुरू कर दी। उनकी धमाकेदार पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और युवा क्रिकेट में उनके बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर दिखा दिया। मैच की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही। कप्तान आयुश महात्रे तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए और उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। इस शुरुआती झटके ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को परेशान किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने हालात को तुरंत अपने पक्ष में मोड़ दिया। क्रिज़ पर आते ही उन्होंने शुरू में परिस्थितियों को समझने के लिए कुछ गेंदें खेलीं, लेकिन जैसे ही उन्हें भूख लगी, उन्होंने यूएई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। वैभव की पारी की असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी फिफ्टी छक्के से पूरे किए। इसके बाद यूएई की गेंदबाजी लाइन-अप पर पूरी तरह हावी हो गए। टीम को स्थिर करने के बाद उन्होंने आक्रामकता का ऐसा स्तर दिखाया जिसने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। पारी के 16वें ओवर में वैभव का बल्ला मानो आग उगलने लगा। अहमद खुदाद गेंदबाजी करने आए और वैभव ने बिना किसी झिझक के लगातार तीन छक्के जड़ दिए। इस ओवर ने मैच का पूरा मोमेंटम भारत की ओर कर दिया। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर सिंगल-डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और अपने शॉट्स को सोच-समझकर खेलने की रणनीति अपनाई। 18वें ओवर में वैभव ने एक शानदार छक्का लगाया और 92 के स्कोर पर पहुंच गए। फिर 19वें ओवर में उन्होंने दो सिंगल लिए और अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर अपने स्कोर को 98 रन तक पहुंचाया। इस समय तक पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो चुका था। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। उनका यह शतक न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थी बल्कि टीम इंडिया के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी तैयार कर गया।

न्यू चंडीगढ़ में हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन

एजेंसी

न्यू चंडीगढ़। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व पुरुष ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड्स का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दोनों दिग्गज स्टेडियम में मौजूद रहे। इस स्टैंड का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता ने किया। इस दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में पिछले महीने भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। यह महिला सीनियर क्रिकेट टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी। हरमनप्रीत कौर तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जिनके सम्मान में स्टैंड का नाम रखा गया। इससे पहले, झूलन गोस्वामी (ईडन गार्डन्स, कोलकाता) और मिताली राज (एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम) को यह सम्मान मिला था। मुख्यमंत्री और अन्य पीसीए पदाधिकारियों की उपस्थिति में हरमनप्रीत, अमनजोत कौर और हरलीन देओल को 11-11 लाख रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए गए, जबकि विश्व कप जीतने वाली टीम के फील्डिंग कोच मुनीश बाली को 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया।

अलग-अलग कोच रखने पर बोले कपिल देव, क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा हो वही करना चाहिए

एजेंसी

नई दिल्ली : भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम के हाल ही में घर पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अलग-अलग कोच रखने के विचार का समर्थन करने से इनकार कर दिया और कहा कि BCCI को वही कोचिंग स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा हो।

अलग-अलग कोच पर कपिल देव की राय

जब उनसे पूछा गया कि क्या रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच रखना भारत के घर पर टेस्ट में हालिया हार का जवाब हो सकता है? कपिल ने कहा, 'मुझे नहीं पता... मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। आपको सच में अपने दिमाग में ऐसी किसी चीज पर काम करना होगा और सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा हो, उन्हें वही करना चाहिए।'

सोशल-मीडिया के दौर में एथलीट बनना मुश्किल?

1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान कपिल ने इस बात को खारिज कर दिया कि सोशल-मीडिया के दौर में एथलीट बनना उनके खेलने के दिनों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा, 'नहीं, यह हमेशा एक जैसा ही होता है। तब भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। तब भी आसान था और अब भी आसान है। आपकी मानसिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है।'

IPL से ज्यादा भारत के लिए खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण

जब उनसे पूछा गया कि क्या टी20 लीग के बढ़ते वित्तीय आकर्षण ने राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व को पीछे छोड़ दिया है तो कपिल ने कहा कि हर खिलाड़ी अपनी प्राथमिकताओं को अलग-अलग तरह से देखता है। उन्होंने कहा, 'हर किसी को पैसा पसंद है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अब भी लगता है कि IPL खेलने से ज्यादा भारत के लिए खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हर कोई अलग-अलग होता है, उनकी अपनी सोच होती है। उन्हें शुभकामनाएं।'

कोन सा फॉर्मेट पसंद है कपिल को

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई खास फॉर्मेट पसंद है? कपिल ने कहा कि उन्हें बस खेल के सभी रूपों में मजा आता है। उन्होंने कहा, 'मुझे बस क्रिकेट पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो गेंदों का क्रिकेट हो या 100 गेंदों का या 100 ओवर का या 10 ओवर का... क्रिकेट तो क्रिकेट है। देखिए गोल्फ तो गोल्फ है, आप कोई भी फॉर्मेट खेलें, दिन के आखिर में आप गोल्फ का आनंद लेते हैं।'

विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर जवाब

उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी भी की। कपिल जो फिलहाल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अध्यक्ष हैं, ने मजाक में कहा, 'शुभकामनाएं, उन्हें गोल्फ भी खेलना चाहिए।'

भारत को ऐसे गोल्फरों की जरूरत है जो बड़े वैश्विक खिताब जीत सकें

कपिल '72 द लीग' के लॉन्च पर बोल रहे थे, जो PGTI द्वारा घोषित एक शहर-आधारित गोल्फ इवेंट है और अगले साल होने वाला है। पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत को ऐसे गोल्फरों की जरूरत है जो बड़े वैश्विक खिताब जीत सकें ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को देखने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सके। उन्होंने कहा, 'हमें वर्ल्ड चैंपियन तैयार करने हैं। जब वे जाकर यूरोपियन कप या US कप जीतेंगे, या ओलंपिक में जीतेंगे, तो पूरा माहौल बदल जाएगा।' गोल्फ के '1983 मोमेंट' के बारे में कपिल ने कहा, 'ये लड़के जाकर यूरोपियन कप या US ओपन जीतें, कुछ ऐसा हो... वह सोने पे सुहागा होगा। ओलंपिक में हम बस मेडल से चूक गए। जब हमारे देश में मुट्ठी भर लोग ही खेल रहे हैं और फिर भी हम वहां तक पहुंचे, तो इससे उम्मीद जगती है। एक दिन हमारे बच्चे जाकर ओलंपिक या S कप जीतेंगे। टेनिस में अगर आप विंबलडन जीतते हैं, तो फर्क पड़ता है; गोल्फ में भी ऐसा ही है।'

रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर

एजेंसी

मुंबई। वाणिज्यिक बैंकों के डॉलर की खरीद बढ़ाने से रुपये पर दबाव रहा और यह 37.50 पैसे टूटकर 90.32 रुपये प्रति डॉलर के नये निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा पिछले कारोबारी दिवस पर सात पैसे नीचे 89.94 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई थी।यह आज 89.95 रुपये प्रति डॉलर पर स्थिर खुली और लगातार टूटते हुए 90.48 रुपये प्रति डॉलर तक उतर गयी जो बीच कारोबार का इसका निचला स्तर है। कारोबारियों ने बताया कि बैंकों की तरफ डॉलर की खरीद बढ़ने से रुपये पर दबाव रहा। हालांकि अन्य सभी कारकों ने इसे समर्थन दिया। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में गिरावट रही। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी से रुपये को कुछ समर्थन मिला। इससे पहले बीच कारोबार का रुपये की निचला स्तर 04 दिसंबर 2025 को 90.43 रुपये प्रति डॉलर रहा था जबकि बंद भाव के मामले में ऐतिहासिक निचला स्तर 03 दिसंबर 2025 को 90.15 रुपये प्रति डॉलर दर्ज किया गया था।

चावल, गेहूं मजबूत; चीनी, दालों, खाद्य तेलों में नरमी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में चावल के औसत भाव बढ़ गये। चावल के साथ गेहूं भी मजबूत हुआ। वहीं, चीनी, दालों और खाद्य तेलों में नरमी देखी गयी। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत तीन रुपये बढ़कर 3,854.01 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। गेहूं दो रुपये महंगा हुआ और 2,852.57 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत सात रुपये टूट गयी। दाल-दलहनों में नरमी रही। चना दाल औसतन 24 रुपये और तुअर दाल 18 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। उड़द दाल और मूंग दाल 17-17 रुपये टूट गयी। मसूर दाल 12 रुपये प्रति क्विंटल कमजोर हुई।विदेशों में बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का फरवरी वायदा एक रिंगिट चढ़कर 4,064 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। वहीं, जनवरी का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.63 प्रतिशत गिरकर में 50.77 डॉलर के भाव बोला गया। स्थानीय बाजारों में सरसों तेल औसतन 80 रुपये और वनस्पति 86 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। मूंगफली तेल की कीमत 73 रुपये और सोया तेल की 67 रुपये प्रति क्विंटल घट गयी। पाम ऑयल 10 रुपये और सूरजमुखी तेल चार रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया। मीठे के बाजार में आज गुड़ की औसत कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल गिर गयी। चीनी भी पांच रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई।

अमेरिकी प्रतिबंध के दबाव से घटा रूसी तेल निर्यात, मॉस्को का राजस्व घटकर 11 अरब डॉलर पहुंचा

नई दिल्ली। अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों के कारण नवंबर में रूसी तेल निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बताया कि प्रतिबंधों की चिंताओं की वजह से खरीदारों पर दबाव पड़ा। एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवंबर में रूसी तेल निर्यात में 420 किलो बैरल प्रति दिन (केबी/डी) की गिरावट आई। कम शिपमेंट और कमजोर कीमतों के संयोजन ने मॉस्को के तेल राजस्व को घटाकर 11 अरब डॉलर कर दिया, जो एक साल पहले की तुलना में 3.6 अरब डॉलर कम है। आईईए ने कहा कि रूस का कुल तेल निर्यात नवंबर में लगभग 400 किलो बैरल प्रति दिन घटकर 6.9 माइक्रोमीटर प्रति दिन हो गया, क्योंकि खरीदारों ने अधिक कड़े प्रतिबंधों से जुड़े प्रभावों और जोखिमों का आकलन किया। निर्यात में गिरावट के कारण यूराल कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट आई, जो 8.2 डॉलर/बैरल (बैरल का अर्थ लगभग 159 लीटर) गिरकर 43.52 डॉलर/बैरल हो गई। इससे निर्यात राजस्व फरवरी 2022 में यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि अमेरिका ने कई देशों को चेतावनी दी है कि अगर वे रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क और दंडात्मक व्यापार उपायों का सामना करना पड़ सकता है।

2047 तक विनिर्माण में पावरहाउस बन जाएगा भारत

नई दिल्ली। घरेलू विनिर्माण को लेकर भारत की नई रणनीति से इस क्षेत्र का योगदान 2047 तक देश की जीडीपी में बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगा।अभी यह करीब 17 फीसदी है। नई रणनीति के दम पर भारत 2047 तक विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पावरहाउस बन जाएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) एवं वेंचर कैपिटल फर्म जेड47 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विनिर्माण रणनीति असेंबली आधारित विकास से हटकर टेक्नोलॉजी आधारित मूल्य सृजन की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट में पांच उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो 2047 तक भारत को 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर, रक्षा, ऊर्जा, फार्मा और ऑटोमोटिव एवं इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये क्षेत्र मजबूत विकास, उद्योग को प्रोत्साहन और स्पष्ट नीति/निवेश योजना का संयोजन करते हैं। यह 2047 तक घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी को करीब 25 फीसदी तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में एथर एनर्जी ने बनाया रिकॉर्ड, 2 लाख की बिक्री पार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में एथर एनर्जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरे उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी के फैमिली-फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather Rizta ने 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है और यह उपलब्धि उसने बेहद कम समय–सिर्फ छह महीनों–में हासिल की है। मई 2025 में 1 लाख यूनिट सेल का पड़ाव पार करने के बाद दिसंबर तक यह संख्या सीधे दोगुनी हो गई, जिससे साफ दिखता है कि यह मॉडल देशभर के ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है। एथर एनर्जी ने बताया कि उसकी कुल बिक्री में से 70फीसदी से अधिक हिस्सा सिर्फ Ather Rizta का है। इसका इतना बड़ा योगदान यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में परिवार-केंद्रित मॉडल की मांग तेजी से बढ़ रही है और खरीदार भरोसे के साथ इस स्कूटर की ओर रुख कर रहे हैं।

दक्षिण भारत से आगे बढ़कर पूरे देश में मजबूत पकड़

रिज्टा के लॉन्च के बाद एथर की पकड़ दक्षिण भारत के बाहर भी तेजी से मजबूत हुई है। कई राज्यों में कंपनी का मार्केट शेयर दोगुना हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह 7फीसदी से बढ़कर 14फीसदी तक पहुंच गया है। पंजाब में इसे 8फीसदी से 15फीसदी का मार्केट मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4फीसदी से बढ़कर अब यह 10फीसदी तक पहुंच चुका है। यह विस्तार बताता है कि रिज्टा ने न सिर्फ कंपनी को नए ग्राहकों से जोड़ा, बल्कि देश के मिड और नॉर्थ इंडिया में एथर की पहचान को और मजबूत किया।

5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने का रिकॉर्ड भी किया हासिल

एथर एनर्जी ने हाल ही में भारत में अपने कुल इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का आंकड़ा 5 लाख के पार होते हुए देखा है। लॉन्च के बाद कंपनी ने अपनी रिटेल पहुंच को भी तेजी से बढ़ाया और सितंबर 2025 तक देशभर में 524 एक्सपीरियंस सेंटर शुरू कर लिए। इससे ग्राहकों की पहुंच और भरोसे दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

रिज्टा की मांग बढ़ाने में नए कलर ऑप्शन और बैटरी वैरिएंट की भूमिका काफी अहम रही। इसका टेराकोटा रेड विकल्प ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ। इसमें 3.7 फीसदी बैटरी वाला Rizta S वैरिएंट मिलता है, जिसमें बड़ा कम्फर्टेबल सीट, 56 लीटर का स्मार्ट स्टोरेज, 34 लीटर अंडरसीट और 22 लीटर फ्रंक (ऑप्शनल) मिलता है। बड़ा फ्लोरबोर्ड इसे खासतौर पर परिवार के उपयोग के लिए और भी प्रैक्टिकल बनाता है।

एथर ने रिज्टा में कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो सुरक्षा और उपयोगिता को काफी बढ़ाते हैं। इसमें Emergency Stop Signal, Theft & Tow Alerts और Ping My Scooter जैसे फीचर्स शामिल हैं। Ather Community Day 2025 में Rizta Z वैरिएंट के लिए टचस्क्रीन अपग्रेड की घोषणा भी की गई। कंपनी ने इस मॉडल को नेपाल और श्रीलंका जैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी लॉन्च किया है।

गोल्ड-सिल्वर रेट में जबरदस्त उछाल

एजेंसी

नई दिल्ली। 12 दिसंबर को भारतीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर घटाए जाने के फैसले के बाद सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर तरजीह मिली है। इस तेजी के कारण, राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,910 प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,213.12 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। सोने की तरह, चांदी के भाव में भी 12 दिसंबर को भारी तेजी दर्ज हुई। चांदी का भाव 2,01,100 प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक, चांदी की कीमतों में 116.72 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जो इसे रिटर्न के मामले में सोने से भी बेहतर साबित करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक सप्लाई में कमी और चीन से बढ़ती मांग के कारण चांदी की चमक बढ़ी है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में इस साल अब तक 67फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और रुपये-डॉलर की विनिमय दर लगभग समान बनी रहती है, तो 2026 में भी सोने की कीमत 5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक और बढ़ सकती है। यह रुझान कीमती धातुओं के मजबूत भविष्य को दर्शाता है।

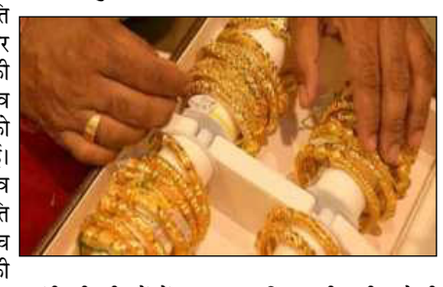

रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी

एजेंसी

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग तंत्र में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास के तहत खुले बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 05 दिसंबर को मौद्रिक नीति संबंधी बयान जारी करने के अवसर पर बताया था कि केंद्रीय बैंक इस महीने एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इससे बैंकों के पास ज्यादा नकदी उपलब्ध होगी और वे ज्यादा ऋण दे सकेंगे। पहले चरण के तहत आज 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति खरीदी गयी है जबकि 18 दिसंबर को इतने ही मूल्य की प्रतिभूतियां खरीदी जायेंगी। ये प्रतिभूतियां चार से लेकर 25 साल तक की मियाद वाली हैं। रिजर्व बैंक की जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि उसने 6.75 प्रतिशत पर 2029 की 6,638 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां

खरीदी हैं। इसके अलावा 7.02 प्रतिशत की दर पर 2031 की 15,316 करोड़ रुपये की और 7.26 प्रतिशत पर 2032 की 21,189 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां खरीदी हैं। केंद्रीय बैंक ने 6.79 प्रतिशत की दर पर 2034 की 1,033 करोड़ रुपये की और 7.54 प्रतिशत पर 2036 की 3,942 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी हैं। साल 2039 में मियाद पूरी करने वाली 657 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां 6.92 प्रतिशत पर और साल 2050 में मियाद पूरी करने वाली 1,225 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां 6.67 प्रतिशत की दर पर खरीदी गयी हैं।

5जी की दौड़ में जियो सबसे आगे, 23 करोड़ ग्राहक जोड़े, होम इंटरनेट में भी सबसे तेज़ बढ़त

एजेंसी

नई दिल्ली। जयो देश में 5जी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। CLSA की नई रिपोर्ट बताती है कि अब तक 23 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जियो के 5जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, कोई भी भारतीय ऑपरेटर इतनी बड़ी तादाद में 5जी यूजर नहीं जोड़ सका है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो का 5त स्टैंड-अलोन नेटवर्क पूरे देश में सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे बेहतर है, और इसी नेटवर्क के दम पर जियो को 5जी की दौड़ में सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। कंपनी के कुल 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों में से करीब आधे अब 5जी सर्विस पर शिफ्ट हो चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक जियो और एयरटेल मिलकर देश में 40 करोड़ से अधिक 5त उपयोगकर्ता जोड़ चुके हैं, और भारत के मोबाइल डेटा बाजार में इन दोनों कंपनियों की सम्मिलित राजस्व हिस्सेदारी 81फीसदी तक पहुंच गई है। 5जी शुरू होने के बाद से बाजार की अधिकतर वृद्धि इन्हीं दो कंपनियों के हिस्से में आई है। इसमें से भी जियो

ने 5जी के क्षेत्र में लीडर की भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 5त स्मार्टफोन की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। यह अब 91फीसदी का आंकड़ा छू चुकी है। 5जी के तेज़ नेटवर्क विस्तार को इसने और मजबूती दी है।

जियो केवल मोबाइल 5जी में ही नहीं, बल्कि घरों में इंटरनेट पहुंचाने की श्रेणी में भी सबसे आगे निकल गया है। कंपनी के पास 2.3 करोड़ होम ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं, और इनमें से 95 लाख घर अब जियो के 5G FWA (Fi&ed Wireless Access) यानी जियोएयरफाइबर पर चल रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य जियोफाइबर व जियोएयरफाइबर से 10 करोड़ ग्राहकों को जोड़ने का है। जियो का 5G FWA देश में होम इंटरनेट की तस्वीर तेजी से बदल रहा है और नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है। भारत के लगभग 30 करोड़ घरों में से वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल 4.5 करोड़ घरों तक ही पहुंचा है। ऐसे में इस सेगमेंट में वृद्धि की बहुत बड़ी गुजाइश है।

भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लंबी छलांग को तैयार, 2047 तक जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत 2047 तक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर है, जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी वर्तमान के करीब 17 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत होने का लक्ष्य है। यह जानकारी जारी एक रिपोर्ट में दी गई। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) और जेड47 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स ऐसे 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, जो 2047 तक 25 ट्रिलियन डॉलर के औद्योगिक अवसर का आधार बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर मांग 2022 में 33 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 117 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, अब भारत में बिकने वाले 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं, वित्त वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26

प्रतिशत पर था। यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है।

बीसीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर ईशांग जावा ने कहा, 'यह सिर्फ आकार की बात नहीं है; बल्कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की बात है। अब भारत केवल असेंबल नहीं कर रहा है, बल्कि डिजाइन, इनोवेट (नया खोज) और वैश्विक वैल्यू चेन में योगदान कर रहा है। '

रिपोर्ट में भारत के नोएडा-चेन्नई-होसुर और धोलेरा जैसे क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का उदाहरण दिया गया है, जो निर्माण में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य से 5 साल पहले 50 प्रतिशत तक पहुंचा लिया है। रिपोर्ट में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), डिजाइन को बढ़ाने, प्रतिभा को मजबूत करने, ब्रेन ड्रेन (विदेशों से भारत लौटकर आए विशेषज्ञों) को बढ़ावा देने, वर्ल्ड क्लास क्लस्टर इकोसिस्टम्स और निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के योगदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, ताकि इस विकास को स्थिर किया जा सके और भारत को वैश्विक नेतृत्व में लाया जा सके। जेड47 के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्तो सन्नीग्राही ने कहा, 'आधुनिक निर्माण और डीप-टेक (गहरे तकनीकी) में सफलता प्राप्त करना विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। '

यूडीआईएन के इस्तेमाल से धोखाधड़ी रोकने में मिली मददः आईसीएआई

एजेंसी

नई दिल्ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने बृहस्पतिवार को कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) के इस्तेमाल से 70,000-80,000 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली

है। यूडीआईएन की शुरुआत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने 2019 में की थी। जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी दस्तावेज का सत्यापन करता है तो एक यूडीआईएन सृजित होता है। नंदा ने राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2019 से अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा यूडीआईएन सृजित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, ''यूडीआईएन के इस्तेमाल से 70,000-80,000 करोड़ रुपये की संभावित धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली है।' यूडीआईएन की व्यवस्था शुरू होने से दस्तावेजों के सत्यापन और पहचान में मदद मिलती है।

सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन में नेस्ट-02 फेज 2 का गोयल ने किया उद्घाटन

एजेंसी

मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) में नेस्ट-02 (न्यू एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज टावर - फेज 2) का उद्घाटन किया और उद्योगों से भारत की भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास पहलों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का आग्रह किया।

वाणिजय मंत्रायल की एक विज्ञप्ति के अनुसार श्री गोयल ने इस अवसर पर जोर दिया कि विकास की गति को एसईईपीजेड में भी बरकरार रखा जाना चाहिए, और कहा कि जोन को अपने कामकाज और प्रदर्शन को मोदी सरकार के नेतृत्व में प्राप्त व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक गति के अनुरूप ढालना होगा। उन्होंने सक्षम युवाओं के लिए पहलों सहित प्रशिक्षण प्रयासों का विस्तार करने के लिए एसईईपीजेड इकाइयों को प्रोत्साहित किया और कहा कि कौशल विकास भारत के भविष्य के विकास के लिए केंद्रीय महत्व रखता। उन्होंने इस क्षेत्र की इकाइयों को प्रशासन के साथ मिलकर एसईईपीजेड के परिचालन को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह बानने का आह्वान किया और कहा कि कामकाज का अच्छा वातावरण बनाये रखना एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने जगह का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए नीलामी आधारित आवंटन और पारदर्शी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं।

उन्होंने हितधारकों को अप्रयुक्त भूखंडों की सामूहिक समीक्षा करने और निर्यात क्षमता को अधिकतम करने के लिए प्रबंध समिति के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने अनुमोदन, सीमा शुल्क संचालन, रखरखाव अनुबंध और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गोयल ने ने एसईईपीजेड में चल रहे और नियोजित बुनियादी ढांचागत उन्नयन कार्यों की समीक्षा की, जिसमें आंतरिक सड़कों, हरियाली और समग्र क्षेत्र-स्तरीय सौंदर्यीकरण में सुधार शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसईईपीजेड आधुनिक भारत के मानकों को प्रतिबिंबित करे और देश भर के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक आदर्श बने।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एसईईपीजेड से भारत के आर्थिक परिवर्तन की गति और महत्वाकांक्षा को रेखांकित करते हुए हुए विश्व इसे स्तरीय उत्पादन और निर्यात क्षेत्र के रूप में उभरने का आह्वान किया। उन्होंने उद्योग-आधारित विकास, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

भारत में वेल्थ क्रिएशन का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा

मार्केट कैप में 148 लाख करोड़ रुपये का उछाल, बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था ने पिछले पाँच वर्षों (2020-2025) में एक अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया है। कोविड-19 महामारी के बाद हुए इस तेज सुधार ने वेल्थ क्रिएशन के पिछले 30 वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOFSL) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में देश की शीर्ष 100 कंपनियों के मार्केट कैप में 148 लाख करोड़ का भारी इजाफा हुआ है। MOFSL की रिपोर्ट बताती है कि इस रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि में वित्तीय क्षेत्र (बैंक और बीमा कंपनियाँ) का योगदान सबसे अधिक रहा है। इसके बाद, उद्योग, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी सेक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकारी कंपनियाँ (PSU), खासकर रक्षा और ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। व्यक्तिगत कंपनियों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने सबसे अधिक संपत्ति बनाई है। इस मजबूत प्रदर्शन के कारण भारत ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब दुनिया का चौथा सबसे

बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन से 16 ट्रिलियन की ओर बढ़ेगी, निवेश के नए और बड़े अवसर पैदा होंगे।

म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया की तिथि टली

एजेंसी

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार के लिए नामांकन ढांचे के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। यह पहले 15 दिसंबर से प्रभावी होने वाला था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा, नई तिथि की घोषणा बाद में होगी। यह स्थगन डिपॉजिटरी और अन्य हितधारकों की ओर से सामना की जा रही परिचालन संबंधी चुनौतियों के जवाब में किया गया है। सेबी ने रीट और इनविट की परिभाषा में भी बदलाव किया है। एक योग्य संस्थागत खरीदार मानी जाने वाली संस्था रणनीतिक निवेशक के रूप में आवेदन कर सकती है। इसमें सरकारी वित्तीय संस्थानों, पेंशन एवं भविष्य निधि, वैकल्पिक निवेश निधि, राज्य औद्योगिक विकास निगम, पारिवारिक ट्रस्ट और 500 करोड़ से अधिक की कुल संपत्ति वाले पंजीकृत मध्यस्थों सहित अन्य संस्थानों का समूह शामिल है।दिग्गज निवेशकों का म्यूचुअल फंड पसंदीदा निवेश का साधन बन चुका है। इसका उदाहरण यह है कि 10,000 करोड़ रुपये के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आईपीओ खुलने से पहले ही 4,815 करोड़ का निवेश किया गया है। खुलने वाले इश्यू में झुनझुनवाला परिवार, मधुसूदन केला सहित 26 निवेशकों ने दांव लगाया है। सक्रिय म्यूचुअल फंड के तिमाही औसत प्रबंधित परिसंपत्तियों के मामले में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देश की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है।

नाबार्ड के सर्वे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय सुधार का दावा

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दो महीनों के सर्वे से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ने से लोगों में जबरदस्त उम्मीद जगी है। सर्वे में 80 फीसदी ग्रामीण परिवारों ने एक साल में लगातार ज्यादा खपत होने की बात कही है।

नाबार्ड के 8वें ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं मत सर्वेक्षण (आरईसीएसएस) के मुताबिक पिछले एक वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में उल्लेखनीय सुधार, आय में बढ़ोतरी और जीवन स्तर में बेहतर बदलाव के स्पष्ट संकेत मिले हैं। एक वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। उपभोग में वृद्धि, आय में बढ़ोतरी, घटती महंगाई और वित्तीय सतर्कता के बेहतर मानकों के साथ ग्रामीण भारत विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। निरंतर कल्याणकारी सहायता और मजबूत सार्वजनिक निवेश इस गति को और बल दे रहे हैं। सितंबर, 2024 से नवंबर 2025 के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय मजबूती दर्ज की गई। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण परिवारों में मासिक आय का 67.3 फीसदी हिस्सा अब उपभोग पर खर्च किया जाता है। यह सर्वेक्षण शुरू होने के बाद का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और इसमें जीएसटी दरों में सुधार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण परिवारों में से 42.2 फीसदी ने अपनी आय में वृद्धि दर्ज की है, जो अब तक के सभी सर्वेक्षणों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। केवल 15.7 फीसदी लोगों ने किसी भी प्रकार की आय में कमी का उल्लेख किया है, जो अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। भविष्य की संभावनाएं काफी मजबूत नजर आ रही हैं, जिसमें 75.9 फीसदी लोगों को उम्मीद है कि उनकी आय अगले वर्ष बढ़ेगी जो सितंबर 2024 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर का आशावाद है। पिछले वर्ष की तुलना में 29.3 फीसदी परिवारों में पूंजी निवेश में वृद्धि देखी गई है, जो पिछले किसी भी चरण में अधिक है जो कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में संपत्ति सृजन में नई तेजी को दर्शाता है। निवेश में यह तेजी मजबूत उपभोग और आय में वृद्धि के कारण है, न कि ऋण संकट के कारण।

58.3 फीसदी ग्रामीण परिवारों ने केवल औपचारिक ऋण स्रोतों का ही उपयोग किया है जो अब तक के सभी सर्वेक्षणों में अब तक का सबसे उच्च स्तर है। सितंबर 2024 में यह 48.7 फीसदी था। हालांकि, अनौपचारिक ऋण का हिस्सा लगभग 20 फीसदी है, जो यह दर्शाता है कि औपचारिक ऋण की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। औसत मासिक आय का 10 फीसदी हिस्सा सब्सिडी वाले भोजन, बिजली, पानी, खाना पकाने की गैस, उर्वरक, स्कूल सहायता, पेंशन, परिवहन लाभ और अन्य कल्याणकारी हस्तांतरणों के माध्यम से प्रभावी रूप से पूरा हो रहा है। कुछ परिवारों के लिए, अंतरित धनराशि कुल आय के 20 फीसदी से अधिक तक होती है, जो आवश्यक उपभोग सहायता प्रदान करती है और ग्रामीण मांग को स्थिर करने में मदद करती है। महंगाई के बारे में औसत धारणा घटकर 3.77 फीसदी हो गई। सर्वेक्षण शुरू होने के बाद यह पहली बार 4 फीसदी से नीचे आई है। 84.2 फीसदी लोगों का मानना है कि महंगाई 5 फीसदी या उससे कम रहेगी और लगभग 90 फीसदी लोगों को उम्मीद है कि निकट भविष्य में महंगाई 5 फीसदी से नीचे ही रहेगी। महंगाई में कमी से वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, क्रय शक्ति में सुधार हुआ है और समग्र कल्याण को बढ़ावा मिला है। कम महंगाई और ब्याज दरों में नरमी के साथ, ऋण चुकाने के लिए आवंटित आय का हिस्सा पहले के दौर की तुलना में कम हो गया है। 29.3 फीसदी ग्रामीण परिवारों में पिछले वर्ष के दौरान पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है ।

जापान से फिजी तक भूकंप के झटके

टोक्यो। शुक्रवार सुबह जापान और फिजी में 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले, उत्तरी जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप से ठीक पहले आसमान में चमकीली नीली रोशनी दिखी थी। जापान और फिजी जैसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में एक बार फिर धरती कांप उठी है। जहां तीन दिन पहले जापान 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जूझ रहा था, वहीं शुक्रवार को इन दोनों क्षेत्रों में 5.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, टोक्यो के निकट और फिजी में ये भूकंप आए। इन हालिया घटनाओं के साथ ही, उत्तरी जापान में भूकंप से पहले आसमान में एक रहस्यमय चमकीली नीली रोशनी दिखाई दी, जिसने वैज्ञानिक समुदाय में दिलचस्पी बढ़ा दी है।

वियतनाम में अप्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला संशोधन पारित

हनोई। वियतनामी संसद ने भूविज्ञान और खनिज कानून में संशोधन पारित कर दिया है, जिसके तहत अप्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा तत्वों का निर्यात प्रतिबंधित हो जाएगा और इन तत्वों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। एक स्थानीय मीडिया वीएनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी 2026 से लागू होने वाले संशोधन के तहत दुर्लभ मृदा तत्वों को रणनीतिक संसाधन का दर्जा दिया गया है। इसके सर्वेक्षण, खनन और प्रसंस्करण सभी कुछ राष्ट्रीय दुर्लभ मृदा तत्वों संशोधित कानून, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ मैटेरियल्स) को एक रणनीतिक संसाधन के रूप में दर्ज करता है। इसके तहत सभी सर्वेक्षण, खनन और प्रसंस्करण गतिविधियाँ राष्ट्रीय दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों की रणनीति और मास्टर प्लान के अनुसार ही की जाएंगी। कानून के अनुसार, केवल राज्य द्वारा नामित संगठन और उद्यम ही इन खनिजों का अन्वेषण, उत्खनन और प्रसंस्करण कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार केवल भूवैज्ञानिक डेटा का प्रबंधन करेगी व्यापार को नियंत्रित करेगी और उचित भंडार बनाए रखेगी। इस संशोधन में अनुसंधान और उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम के पास दुर्लभ मृदा तत्वों के लगभग 3.5 लाख टन भंडार हैं और यह वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है।

पूर्व आईएसआई चीफ़ हमीद को 14 साल की कैद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख फैज़ हमीद को कई मामलों में दोषी पाये जाने के बाद 14 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत शुरू हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने बयान में कहा कि 15 महीने की सुनवाई के बाद उनके लिये यह सज़ा तय की गयी है। हमीद को राजनीतिक कार्यों में शामिल होने, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की हद तक शासकीय गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने, सरकारी संसाधनों एवं प्राधिकार का दुरुपयोग करने और व्यक्तियों को 'गलत नुकसान' पहुंचाने के आरोप में दोषी पाया गया। बयान में कहा गया है कि 'राजनीतिक तत्वों के साथ मिलकर राजनीतिक अशांति और अस्थिरता भड़काने' में उनकी कथित भूमिका पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) फैज हमीद पाकिस्तान सेना के एक पूर्व उच्च-रैंकिंग अधिकारी थे। वह जून 2019 से अक्टूबर 2021 तक आईएसआई के 29वें महानिदेशक रहे थे। पंजाब के चकवाल में जन्मे हमीद पाकिस्तान सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण के बाद 1987 में बलूच रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने आईएसआई के 'काउंटर-इंटेलिजेंस विंग' के प्रमुख (2017-2019) होने के अलावा भी कई अहम भूमिकाएं निभाईं। हमीद को 2017 के फैजाबाद धरने के समाधान और तालिबान के कब्ज़े के बाद 2021 में काबुल की यात्रा के दौरान पहचान मिली थी।

कनाडा में विपक्ष को बड़ा झटका: कंजरवेटिव सांसद माइकल मा ने छोड़ी पार्टी

कनाडा। कनाडा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां कंजरवेटिव पार्टी के सांसद माइकल मा ने अपनी पार्टी छोड़कर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल सरकार का दामन थाम लिया। माइकल मा ओंटारियो प्रांत की मार्कहम-यूनियनविल सीट से सांसद हैं। वे पिछले एक महीने में दूसरे कंजरवेटिव सांसद हैं जिन्होंने लिबरल पार्टी ज्वॉइन की है। बात अगर माइकल मा के पार्टी छोड़ने के पीछे की कारण की करें तो अपने बयान में मा ने कहा कि वे राजनीति में 'समाधान ढूंढने, न कि विभाजन बढ़ाने के लिए आए थे। मा ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वह स्थिर और व्यावहारिक नेतृत्व दे रहे हैं जिसकी देश को जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे अपने इलाके के लोगों से रोजाना जिन समस्याओं के बारे में सुनते हैं, उन पर काम करने में कार्नी की सरकार बेहतर है।

बता दें कि मा के शामिल होते ही लिबरल पार्टी संसद में बहुमत से सिर्फ एक सीट कम रह गई है। ऐसे में अगर वे बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें अपने बिल पास कराने के लिए किसी विपक्षी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर माइकल मा के इस कदम से कंजरवेटिव पार्टी के खेमे में नाराजगी का माहैल है। कंजरवेटिव नेता पियरे पोलीएव्रे ने अपनी नाराजगी जारी करते हुए कहा कि माइकल मा को उनके क्षेत्र के लोगों ने लिबरल सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध करने के लिए चुना था। लेकिन आज वे उन्हीं नीतियों का समर्थन करने चले गए।

यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा के लिए संरा के डब्ल्यूएफपी को दिया 290 लाख डॉलर का योगदान

एजेंसी

मास्को। यूरोपीय संघ ने अफ़गानिस्तान में खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को 250 लाख यूरो (293 लाख डॉलर) प्रदान किया है। अफ़गानिस्तान में ईयू के प्रभारी डी'अफेयर्स वेरोनिका बोस्कोविक-पोहर ने यह जानकारी दी।

एरियाना न्यूज़ पोर्टल ने श्री बोस्कोविक-पोहर के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा, 'डब्ल्यूएफपी में यूरोपीय संघ का नया योगदान अफ़गानिस्तान के लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और कमज़ोर स्थानीय समुदायों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखला को अफ़गानिस्ता के लोगों के पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक लचीलापन को मज़बूत करने के लिए तैयार

किया जाना चाहिए। जलवायु लचीलापन के लिए हम अपने संकलित दृष्टिकोण कमज़ोर ग्रामीण समुदायों को प्राकृतिक आपदाएँ और जलवायु परिवर्तन के लंबे समय तक चलने वाले खतरनाक असर से उनकी रोजी-रोटी और आमदनी को बचाने में भी मदद कर रहे हैं।' रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वित्त पोषण डब्ल्यूएफपी की उन कोशिशों को मदद करेगी जिनका मकसद खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की श्रृंखला को बेहतर बनाना और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष परियोजनाओं में बाढ़ से बचाने वाली दीवारें और सिंचाई प्रणाली जैसे अवसंरचना को अद्यतन करना, जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करना और स्थानीय आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी उत्पादक संपत्तियों की सुरक्षा करना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश का एक बड़ा हिस्सा डब्ल्यूएफपी के विद्यालय वित्त पोषण कार्यक्रम को विकसित करने और महिला संगठनों और युवा उद्यमियों को स्कूली बच्चों को ताज़ा राशन आपूर्ति करने के लिए प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यूनुस पर लगाए गंभीर आरोप, 'हाशिए पर धकेला, अपमानित किया जा रहा है'; चुनाव के बाद देंगे इस्तीफा

एजेंसी

नई दिल्ली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हाल ही में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि वह फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव के बाद अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा अपमानित और साइडलाइन किया जा रहा है। शहाबुद्दीन को 2023 में अवामी लीग के उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने बताया कि पिछले सात महीनों में उनकी यूनुस से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसके अलावा, उनके प्रेस विभाग को हटा दिया गया और सितंबर में बांग्लादेश के सभी दूतावासों और मिशनों से उनकी तस्वीरें हटा दी गईं। राष्ट्रपति ने इसे बहुत अपमानजनक बताया। शहाबुद्दीन ने कहा कि उनकी आवाज को दबा दिया गया है और वह अब इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह केवल संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत पद पर बने हुए हैं, और चुनाव के बाद ही पद छोड़ेंगे। उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल में एक नई चर्चा का कारण बनी है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बिगड़ी

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत और बिगड़ गई। किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। खालिदा का इलाज राजधानी ढाका के एवरकेयर अस्पताल में चल रहा है। बीएनपी नेत्री खालिदा लंबे समय से बीमार चल रही हैं। 23 नवंबर से इस अस्पताल में भर्ती 80 वर्षीय खालिदा जिया को इस वक्त इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट का मतलब है कि योजनाबद्ध तरीके से या सर्जरी से पहले मरीज को सांस लेने वाली मशीन (वेंटिलेटर) का सहारा देना। जब डॉक्टर को पता होता है कि एनेस्थीसिया या ऑपरेशन के कारण मरीज खुद से सांस नहीं ले पाएगा। इलेक्टिव एक योजनाबद्ध और पूर्व तय चिकित्सा प्रक्रिया है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रात से खालिदा जिया की हालत कुछ ज्यादा गंभीर है। उनका सावधानी से इलाज चल रहा है। उनके उच्च इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड कहा कि उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें नियमित डायलिसिस की जरूरत है। मेडिकल बोर्ड की ओर से प्रो. डॉ. शहाबुद्दीन तालुकदार ने गुरुवार देररात स्थिति का विश्लेषण करते हुए बयान जारी किया है। इसमें लोगों से जिया के बारे में अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। बयान में कहा गया है कि उन्हें सांस लेने में अधिक दिक्कत हो रही है। खून में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। उनका इलाज हाई-फ्लो नेजल कैनुला और बाइपैप मशीन से किया जा रहा है। यह मशीन मास्क के जरिए हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि क्योंकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उनके फेफड़ों और दूसरे अंगों को आराम देने के लिए उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। मेडिकल बोर्ड के अनुसार, 27 नवंबर को इलाज के दौरान एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पता चला। उसका अभी भी इंटेंसिव इलाज चल रहा है। गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें एडवांस्ड एंटीबायोटिक और एंटीफंगल थेरेपी दी जा रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन (डीआईसी) के कारण उन्हें खून और उसके कंपोनेंट्स का ट्रांसफ्यूजन भी दिया जा रहा है। इन सभी इलाज के बावजूद उनका बुखार बना हुआ है। रेगुलर इकोकार्डियोग्राफी के दौरान उनके एओर्टिक वाल्व में कुछ दिक्कतें देखी गई हैं। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से सलाह लेकर इलाज शुरू कर दिया है।

पुर्तगाल के कलाकारों ने कहा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीते तो यूरोविज़न का करेंगे बॉयकॉट

एजेंसी

लिस्बन। आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और स्लोवेनिया के यूरोविज़न 2026 से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के सॉन्ग सिलेक्शन कॉन्टेस्ट 'फेस्टिवल दा कैंकाओ' में 17 पुर्तगाली कलाकारों ने घोषणा की है कि अगर वे जीतते हैं तो वे भी इस आयोजन का बॉयकॉट करेंगे। प्रतिनिधि चुनने के लिये हुए अंदरूनी मुकाबले में हिस्सा लेने वालों ने एक बयान जारी कर मुकाबले में इजरायल की विवादित भागीदारी का विरोध किया। हस्ताक्षर करने वालों में क्रिस्टीना ब्रैंको, बटेउ माटो, रीटा डायस, जोडीजे, बीट्रिज़ ब्रॉन्ज़ (एवाया), फ्रांसिस्को फोंटेस, गोंकालो गोम्स, इनेस सूसा, जॉर्ज गोंकाल्वेस (जकारेउ), मार्क्विस, नुंका मेट्स ओ मंदारिम और पेड्रो फर्नांडीस शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'शब्दों और गानों के ज़रिए हम उन संभावनाओं के दायरे में काम करते हैं, जो हमें दी गयी हैं। हम मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल होना स्वीकार नहीं करते। 'कलाकारों ने कहा, ' राजनीतिक कारणों (यूक्रेन पर हमले) से रूस को यूरोविज़न 2022 से बैन किये जाने के बावजूद, हमें यह देखकर हैरानी हुई कि इज़रायल के प्रति ऐसा रुख नहीं अपनाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम कर रहा है। ' पुर्तगाल के ब्रॉडकास्टर आरटीपी ने कलाकारों की बातों के जवाब में एक बयान जारी कर कहा है, ' बयान पर हस्ताक्षर करने वाले कलाकारों के फैसले की परवाह किये बिना, आरटीपी एक बार फिर 'फेस्टिवल दा कैन्साओ' का आयोजन करेगा और यूरोविज़न गायन प्रतियोगिता 2026 में अपनी भागीदारी की पुष्टि करता है। 'यूरोविज़न जीतने वाले एकमात्र पुर्तगाली कलाकार साल्वाडोर सोब्राल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में आरटीपी के रुख की आलोचना की, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली ब्रॉडकास्टर पर 'राजनीतिक कायरता' का आरोप लगाया। यह गुस्सा पुर्तगाल की जनता तक भी पहुंच गया है, जिन्होंने यूरोविज़न से पुर्तगाल के तुरंत बाहर निकलने की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है। पहले ही 22,000 से ज़्यादा लोग इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि आरटीपी का इज़रायल की भागीदारी के पक्ष में वोट 'पुर्तगाल को इतिहास के गलत छोर पर खड़ा करता है।' पिछले हफ़्ते, यूरोपीय प्रसारण यूनियन (ईबीयू) ने यूरोविज़न 2026 में इज़रायल की भागीदारी की पुष्टि की। ईबीयू की महासभा में इज़रायल की भागीदारी को लेकर कोई वोट नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और स्लोवेनिया ने पुष्टि की कि वे इस आयोजन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। बीते रोज़ प्रसारक आरयूबी की बोर्ड मीटिंग के बाद आइसलैंड बहिष्कार में शामिल होने वाला पांचवां देश बन गया।

व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क मेयर ममदानी के वीडियो के बाद आईसीई एजेंट्स पर हमलों में बढ़ोतरी की चेतावनी दी

एजेंसी

वाशिंगटन । व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी के हालिया वीडियो की कड़ी आलोचना की है। इस वीडियो में अप्रवासियों को कथित तौर पर 'आईसीई के खिलाफ खड़े होने' के लिए उकसाया गया था। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि ऐसे संदेश फेडरल अप्रवासन अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा में बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन एजेंटों के खिलाफ हिंसा, हमलों और शारीरिक धमकियों में बढ़ोतरी को लेकर निश्चित रूप से चिंतित है। उन्होंने इसे एक चिंताजनक वृद्धि करार दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा, 'हमने उन पर और उनके परिवारों पर हिंसक हमलों में एक हजार प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी है।' लेविट ने कहा कि आईसीई अधिकारी की जानकारी को उजागर किया गया।

उनका उत्पीड़न किया गया है। कई पर शारीरिक रूप से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वे बस हमारे राष्ट्र के अप्रवासन कानूनों को लागू कर रहे हैं। क्या न्यूयॉर्क का संदेश निवासियों को एनफोर्समेंट ऑपरेशन का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'प्रशासन इसकी निंदा करता है और हर राज्य में अमेरिकी समुदायों से अवैध विदेशियों और पब्लिक सेफ्टी के खतरों को हटाने के अपने मिशन को जारी रखेगा। प्रेस सेक्रेटरी की टिप्पणियां तब आई जब रिकॉर्ड-कम एनकाउंटर नंबर का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्तमान सीमा स्थितियों को अमेरिकी इतिहास में सबसे सुरक्षित घोषित किया। लेविट के अनुसार, लगातार सातवें महीने, यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जीरो अवैध विदेशियों को छोड़ा। उन्होंने पिछले प्रशासन से तुलना करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के दस महीनों में, हमने जो बाइडेन के एक महीने के मुकाबले कुल मिलाकर कम डर देखा है।' प्रशासन के इन बयानों ने देश के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख महानगरों में तनाव को भड़काया है, जहां हजारों भारतीय नागरिकों सहित अनेकों कई अप्रवासी रहते और काम करते हैं। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सीमा पर संप्रभुता बहाल की है। उन्होंने आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे तेज राष्ट्रीय सुरक्षा विजय हासिल की है। उन्होंने कहा कि अवैध क्रॉसिंग में निरंतर गिरावट शानदार नतीजे हैं।

म्यांमार में अस्पताल पर जुंटा हवाई हमले में 30 लोगों की मौत

एजेंसी

नेपीडॉ। गृह युद्ध से गुज़र रहे म्यामांर के एक अस्पताल पर हुए सैन्य हवाई हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गयी। मौके पर मौजूद मेडिकल कर्मी ने यह जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हुए इस हमले में जिस हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, वह अराकान सेना के अधीन कई उपनगरों के आम नागरिकों के लिये इलाज का केंद्र बना हुआ था। उल्लेखनीय है कि म्यामांर में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से देश गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। देश के करीब आधे हिस्से पर राज्य प्रशासन परिषद उर्फ जुंटा (सैन्य शासन) का कब्ज़ा है, जबकि बाकी देश अराकान जैसे जातीय सैन्य संगठनों और 'पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस' के अधीन है। जुंटा शासन ने अपने कब्ज़े वाले क्षेत्र में 28 दिसंबर 2025 से तीन चरण में चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है। चुनाव की ओर बढ़ते हुए जुंटा ने हवाई हमलों की संख्या बढ़ा दी है। बीते सिर्फ तीन महीनों में अस्पतालों, गांवों और स्कूलों पर 30 से ज्यादा हवाई हमले किये जा चुके हैं।

वाराणसी से काठमांडु बस सेवा 18 महीने बाद फिर से होगी शुरू, किराया 2 हजार रुपए

एजेंसी

वाराणसी। लगभग 18 महीने से बंद पड़ी वाराणसी-काठमांडु बस सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। नेपाल सरकार के निर्देश पर श्रीमंजूश्री बस सेवा समिति नेपाल ने इस अंतरराष्ट्रीय बस सेवा को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से बंद रहने के कारण व्यापारियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सेवा शुरू होने की घोषणा के बाद लोगों में खुशी है। सेवा 24 दिसंबर से वाराणसी रोडवेज बस स्टेशन से दो नई बसों के साथ शुरू की जाएगी। बस संचालक गौरव कुमार के अनुसार प्रति यात्री 2000 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल बस सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को

चलाई जाएगी, ताकि यात्रियों को नियमित अंतराल पर बेहतर विकल्प मिल सके। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जरूरत पड़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। वाराणसी से बस रात 9 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4 बजे तक काठमांडु पहुंचेगी। इसी तरह काठमांडु से बस शाम 6:30 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 3:30 बजे वाराणसी लौट आएगी। यह समय-सारिणी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने और रास्ते की औपचारिकताएं सुचारू रूप से पूरी हो सकें। करीब डेढ़ साल बंद रहने के दौरान यात्रियों को निजी वाहनों या महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। खासकर नेपाल में रहने वाले व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ीं। अब बस सेवा शुरू होने से एक बार फिर से दोनों देशों के बीच यात्रा, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है।बस संचालकों और यात्रियों का कहना है कि यह सेवा भारत-नेपाल मैत्री का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है, इसलिए इसके पुनः शुरू होने का बड़ा स्वागत किया जा रहा है।

पिछले एक साल में दुनिया भर में 67 पत्रकार मारे गये: आरएसएफ रिपोर्ट

एजेंसी

पेरिस। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में अपने काम के दौरान 67 पत्रकार मारे गये हैं। आरएसएफ ने अपने रिपोर्ट में कहा कि पत्रकार सिर्फ मरते नहीं है, मारे जाते हैं। पत्रकारों की हत्या की संख्या फिर से बढ़ गयी है और इसका कारण नियमित और अर्धसैनिकों की आपराधिक गतिविधियां हैं। इस वर्ष 67 में से 53 पत्रकार युद्ध या आपराधिक समूह द्वारा मारे गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 महीनों में (एक दिसंबर तक) मारे गए पत्रकारों में से लगभग आधे (43 प्रतिशत) को गाज़ा में इज़रायली सशस्त्र बलों द्वारा मारा गया। इसके बाद सबसे अधिक पत्रकार (नौ) मैक्सिको में आपराधिक समूहों द्वारा मारे गये। रिपोर्ट में चिंता जतायी गयी है कि यह पिछले तीन सालों में सबसे अधिक है।तीसरे स्थान पर सूडान है, जहाँ पत्रकारों को काफी मुश्किलों का

सामना करना पड़ता है। इस साल सूडान में चार पत्रकार मारे गये, जिनमें से दो को रैपिड सपोर्ट फोर्स द्वारा अपहरण के बाद मार दिया गया। रिपोर्ट में इस बात पर आश्चर्य जताया गया है कि पत्रकारों को अपने ही देश में अधिक खतरा है। मारे गये पत्रकारों में से केवल दो ही विदेशी धरती पर मारे गये हैं। फ्रांसीसी फ़ोटो पत्रकार एंतोनी ललिकान यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमले में मारे गए थे और साल्वाडोर के पत्रकार हाविएर हेर्कुलेस की होंडुरास में हत्या कर दी गयी थी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के अनुसार, एक दिसंबर 2025 तक 47 देशों में कुल 503 पत्रकार हिरासत में थे। दुनिया में अब भी सबसे ज्यादा पत्रकार (121) चीन के जेलों में बंद हैं। इसके बाद रूस (48) और फिर म्यांमार (47) का स्थान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में, रूस किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक विदेशी पत्रकारों को जेल में रखता है (26), जबकि इसके बाद इज़राइल आता है, जहाँ जेलों में 20 पत्रकार बंद हैं।

पुनर्चक्रित पॉलिस्टर नये पॉलिस्टर की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक खतरनाक

एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स की अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन चेंजिंग मार्केट्स फाउंडेशन के हालिया अध्ययन के मुताबिक फैशन उद्योग में इस्तेमाल होने वाला कथित 'हरित' पुनर्चक्रित पॉलिस्टर नये पॉलिस्टर की तुलना में अधिक प्रदूषण फैला रहा है। संगठन द्वारा फैशन क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों के उत्पादों पर किये गये अध्ययन में पाया गया कि पुनर्चक्रित पॉलिस्टर से बने कपड़ों और अन्य उत्पादों से नये पॉलिस्टर से बने उत्पादों की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक 'माइक्रोप्लास्टिक' पर्यावरण में मुक्त होते हैं। अध्ययन के अनुसार, इन उत्पादों की धुलाई के समय निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक सामान्य की तुलना में 20 प्रतिशत छोटे भी होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक हैं। उल्लेखनीय है कि कई बड़े ब्रांड पुनर्चक्रित पॉलिस्टर को पर्यावरण अनुकूल बताकर तेजी से इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं।

संगठन के अनुसार कई कंपनियाँ 2030 तक पुनर्चक्रित पॉलिस्टर के इस्तेमाल को 100 प्रतिशत तक करने की योजना बना रही हैं। गौरतलब है कि पर्यावरण विशेषज्ञ पर्यावरण में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक को लेकर लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये पर्यावरण में हर जगह फैल चुके हैं और मानव खून में भी पाये जाने लगे हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गयी है।

एआई को 'नेशनल फ्रेमवर्क' में लाने के लिए ट्रंप ने साइन किया ऑर्डर, चीन के उभार पर चेताया

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नियमों को एक जगह से नियंत्रित यानी सेंट्रलाइज करना है। उनका कहना है कि अलग-अलग राज्यों के अपने नियम होने से तकनीकी विकास धीमा पड़ सकता है और चीन के मुकाबले अमेरिका की बढ़त को खतरा हो सकता है। आदेश पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने कहा कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे है। हमारे पास एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, जहां हम चीन से और बाकी देशों से बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा वैश्विक मुकाबला है और इसमें जीत किसी एक की ही होगी,या अमेरिका की या चीन की। फिलहाल अमेरिका बहुत आगे चल रहा है। इस आदेश के ज़रिए सरकार चाहती है कि पूरे देश में एआई के लिए एक ही राष्ट्रीय ढांचा बने। प्रशासन का कहना है कि अगर हर राज्य के अलग नियम होंगे, तो डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश रुक सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर कंपनियों को 50 राज्यों से अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़े, तो विकास असंभव हो जाएगा।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी

ने बताया कि एआई का नेतृत्व आर्थिक विकास, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षमता से सीधा जुड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि यह व्यवस्था एक ही राष्ट्रीय ढांचे में चले।

समारोह में डेविड सैक्स ने कहा कि राज्यों में एआई पर बहुत तेजी से कानून बनाए जा रहे हैं। हजार से ज़्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं और सौ से अधिक पास भी हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में हैं। सैक्स ने कहा कि संघीय सरकार संसद के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करेगी और अत्यधिक सख्त राज्य स्तरीय नियमों पर रोक लगाएगी, जबकि बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान बनाए रखे जाएंगे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने एआई को राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई भी बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने एआई विकास धीमा किया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चीन को लेकर ज्यादा परेशान हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले रिस्क को लेकर, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'दोनों को लेकर।' उन्होंने बताया कि एआई के कारण दवा और चिकित्सकीय शोध में तेज प्रगति हो रही है और तकनीक अपनी शुरुआत के बावजूद उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। यह कार्यकारी आदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने को कहता है कि एआई एक ही राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सुचारू रूप से काम कर सके, न कि अलग-अलग राज्यों के नियमों के कारण बाधित हो।

page 1 and 8_page 1 Mar 25 final ds.qxd 12/12/2025 11:02 PM Page 2

ढ़ींगरी मशरूम की खेती

भारत प्राचीन काल से ही कृशि प्रधान देष है। यहाँ की जलवायु लगभग सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है। इन फसलों से प्राप्त अवषेश, जैसे भुसा, बाजरा, गन्ना, पुआल आदि पयाप्त मात्रा में बच जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में होता है। इसके बावजूद जो अवषेश बच जाते हैं उनका प्रयोग खुम्ब उत्पादन में किया जा सकता है। ढ़ींगरी की खेती बहुत ही आसान और कम खर्चीली है। इसीलिए यह गरीब किसानों के लिए उचित आय का साधन भी है।

ढ़ींगरी का आहार:

ढ़ींगरी का संतुलित आहार के रूप में बड़ा महश्व है। इसमें 17 से 38: प्रोटीन होती है। ढ़ींगरी के प्रोटीन में वे सभी अमिनो एसिड पाए जाते हैं जो मनुश्य के षरीरिक विकास के लिए अति आवष्यक हैं। लवण कैलाषियम फासफोरस, पोटाषियम, आयरन तथा ताँबा भी उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ढ़ींगरी में विटामिल 'बी' काम्प्लैक्स तथा विटामिन 'सी' 80 से 14 मिलीग्राम प्रति सौ ग्राम में पाए जाते हैं। ढ़ींगरी का सेवन मधुमेह हृदय रोग व मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए उपयुक्त भोजन है। भारत में ढ़ींगरी की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जिसमं कुछ ग्रीश्मकालीन और षरदकालीन हैं। इन प्रजातियों की तापमान आवष्यकता निम्नलिखित रूप से दर्षाई गई है।

शरद कालीन प्रजापतियाँ कवकजाल फैलाव के लिए फलन के लिए

1.प्लूरोंटस औसट्रिटस25-30 20-22
2. प्लूरोंटस फ्लोरिडा 25-30 18-22

रसायनिक उपचार:

1. किसी ड्रम में 90 लीटर पानी लेकर 10 किलोग्राम भूसा डुबो लें।

2. इसके साथ ही एक बाल्टी में 125 मि लीटर फार्मलीन और 7.5 ग्राम वैविस्टीन को 10 लीटर पानी में मिला कर घोल बना लें।

3.बाल्टी में बनाए गए रसायनिक घोल को भूसे वाले ड्रम में उड़ेल दें तथा प्लास्टिक षीट से ढक दें।

4. 24 घंटे में बाद ड्रम को साफव पक्के फर्ष पर पलट दें ताकि भूसे से अतिरिक्त पानी निकल जाए और फार्मलीन की महक खत्म हो जाए इस प्रक्रिया में 1-1'' घंटे का समय लग जाता है। 10 किलो ग्राम सूखा भूसा उपचार के बाद लगभग 40 किलोग्राम हो जाता है।

बीजाई करने की विधि:

बीजाई करने से पहले बीजाई स्थल को अच्छी तरफ से फार्मलिन घोल से उपचारिक करें तथा बीजाई करने वाला श्रमिक भी अपने हाथों को साफकरें। इसके बाद उपचारित किए गए भूसे से 25-30 ग्राम प्रति किलो भूसे की दर से बीज मिलाते हैं इसे पालीथीन लिफाफे (18x24'') में भरते हैं तथा इसके बाद इनका मुँह अच्छी तरह से बंद करते हैं। इन लिफाफों के निचले कोनों को थोड़ा सा काट लें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। बीजित बैगों को उत्पादन कक्षा में रख दें। इस उत्पादन कक्ष में 24 घंटे पहले 2: फार्मलिन के घोल से छिड़काव किया जाता है। कमरे का तापमान बीजित की गई प्रजाति के अनुसार और नमी 80-85 प्रतिषत रखना चाहिए। बीजित बैगों में 10-15 पैंसिल की मोटाई के समान छेद कर दें ताकि पालीथीन के बैग के अन्दर ज्यादा गर्मी न हो जाए और साथ में ढ़ींगरी के बीज को फैलने के लिए आवष्यक आक्सीजन भी मिलती रहे। 15 से 20 दिन के पश्चात् जब ढ़ींगरी का सारे भूसे में अच्छी तरह फैल जाए तो पालीथीन के बैगों को काट कर या ऐसे ही निकाल लें और भूसे तथा ढ़ींगरी के बीज से बने ढेले को लकड़ी या बांस के बने फ्रेम के उपर 8 से 12 ईन्च की दूरी पर रख दें और इस बात का ध्यान रखें कि कमरे का तापमान प्रजाति के अनुसार और नमी 80-90 प्रतिषत तक बनी रहे। कमरे में उचित नमी बनाए रखने के लिए ढेलों के उपर तथा फर्ष पर स्प्रे पप्प की सहायता से हल्के पानी का छिड़काव प्रतिदिन करते रहें। पोलीथीन के लिफाफे या बैग का निकालने के पश्चात् प्रतिदिन पानी के छिड़काव के 2-3 घंटे तक प्रकाष को कमरे में आने दें तथा ताजी हवा के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ भी खोल दें। जिस कमरे में प्रकाष न पहुँच सके उसमें बिजली का बल्व या टयूव को दे घण्टे तक जलता रखे।

ढ़ींगरी का अंकुरण तथा देखभाल:

पोलीथीन लिफाफे निकालने से 5 से 7 दिन पश्चात् ढेले में से अंकुरण निकलना षुरू हो जाते हैं और 3-5 दिन के अन्दर तोड़ने योग्य हो जाते हैं जब ढ़ींगरी का आकार 8-12 से.मी. हो जाए तो उसे उंगलियों की सहायता से हल्का सा मरोड़ दे कर तोड़े ले। ढ़ींगरी के निकलने का क्रम लगभग 40-50 दिन तक 8-10 दिन के अंतराल पर चलता रहता है।

ढ़ींगरी की उपज:

यदि कमरे में उचित तापमान और नमी बनाए रखी जाए तो 10 किलो ग्राम सूखे भूसे से 8-9 किलो ग्राम ढ़ींगरी प्राप्त होगी।

आमदनी:

आमदनी की दृश्टि से ढींगरी मुनाफा देती है क्योंकि इसमें कम समय और धन लगता है एक किलोग्राम ढींगरी पैदा करने के लिए 10-15 रूप्ये का खर्च आता है और बाज़ार में यह 30-50 रूप्ये प्रति किलो के भाव से बिकती है, इस प्रकार प्रति किलोग्राम में 15-30 रूप्ये की आमदनी होती है।

ढींगरी की भरपूर फसल लेने के उपाय:

1. रसायनिक विधि द्वारा माध्यम को उपचरित्र करें।
2. ढींगरी वाले कमरे को हमेषा स्वच्छ रखें तथा उसके बाहर भी गन्दगी को इक्ट्ठा न होने दें।
3. लिफाफे के निचले दोनों कोनों को 1'' काट दे ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए।
4. तापमान और नमी को बनाए रखे।
5. ढींगरी को मुड़ने से पहले ही तोड़ लें।
6. जब फ्ल आना षुय होता है दीवारों और फर्श पर 0.5 प्रतिषत मैलाथियान का स्प्रे कर दे ताकि किसी प्रकार का कीट हानिकारक सिद्ध न हो।
7. रोगी या किसी भी बीमारी वाले ब्लाक को कमरे से बाहर निकाल कर जमीन मं गाढ़ दें ताकि बीमारी न फैले।

फसलों पर अनुकूल एवं प्रतिकूल मौसम का प्रभाव

सी एम शर्मा

मौसम किसी स्थान का मौसम असल में उस स्थान के तापमान, बादलों की दशा, हवा में नमी आदि से सम्बंधित है। मौसम का सम्बन्ध हमारे वातावरण में रोजाना होने वाले बदलावों से है।

ये मौसम सब जगहों पर एक जैसा नहीं रहता। किसी एक जगह पर मौसम गर्म और तेज़ धूप वाला हो सकता है वहीं उसी समय किस दूसरी जगह ठंडी हवाओं और बर्फबारी वाला मौसम हो सकता है। वायुमंडल की दशाएं मौसम को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

मौसम तथा कृषि क्रियाएं

मौसम का कृषि क्रियाओं से बहुत गहरा सम्बन्ध है। कृषि में खेत की जुताई, बुवाई, निराई-गुड़ाई फसल की वृद्धि फसल का पकना फसल की कटाई तथा भंडारण तक की सभी क्रियाएं मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करती हैं तथा फसल की सफलता और असफलता मौसम के ऊपर निर्भर करती है।

किसी भी फसल की उपज प्राप्त करने के लिए समय पर फसल की बुवाई होनी चाहिए फिर अंकुरण के लिए उचित धूप वायु तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसके बाद पौधों की वृद्धि के लिए धूप वर्षा और वायु की आवश्यकता पड़ती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए धूप की आवश्यकता है। धूप में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा धूप से भूमि के ताप में वृद्धि होती है जिससे आवश्यक तत्व जल में घुल जाते हैं जिन्हें पौधे अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। धूप में फसलों पर कीड़ों का प्रभाव भी कम होता है।

इसके अतिरिक्त पौधों की वृद्धि हेतु समय-समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है।

यदि इस समय पर वर्षा हो जाती है तो सिंचाई के साथ साथ वायु में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। इसी प्रकार फसल की पकाई, कटाई तथा भंडारण के समय भी अनुकूल मौसम का होना अनिवार्य है।

यही कारण है कि जिस वर्ष मौसम फसलों के अनुकूल होता है, फसलों की पैदावार अच्छी होती है तथा जिस वर्ष मौसम प्रतिकूल होता है उस वर्ष में फसल की पैदावार कम होती है।

फसलों पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव-

प्रतिकूल मौसम फसलों को अंकुरण से लेकर उन के भंडारण तक की क्रियाओं को प्रभावित करता है जिससे उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम मौसम की उन दशाओं का वर्णन करेंगे, जो फसलों पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

त्रुटियुक्त वर्षा - वर्षा की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं-

अनावृष्टि - वर्षा का बहुत कम होना या बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है। ऐसी अवस्था में खरीफ की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। केवल ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहां सिंचाई की सुविधाएं हैं, फसलें सूख जाती हैं और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा रबी की फसलों की बुवाई भी अधिकतर क्षेत्रों में नहीं हो पाती।

अतिवृष्टि - वर्षा का आवश्यकता से अधिक होना अतिवृष्टि कहलाता है वर्षा की इस अवस्था से नदियों में बाढ़ आ जाती है जिससे फसलें बह जाती हैं या पानी में डूबकर सड़ जाती हैं। दूसरे, जो क्षेत्र गहरे होते हैं तथा जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर अधिक दिनों तक पानी भरा रहता है जिसके कारण पौधों की जड़े गल जाती है। इससे खरीफ की फसलों में भारी हानि होती है तथा रबी की फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जमीन की समय पर जुताई नहीं हो पाती है जिससे रबी की फसल की बुवाई देर से होती है।

असमय वृष्टि - जब वर्षा ठीक समय पर ना होकर ऐसे समय पर होती है जब वर्षा की आवश्यकता न हो तो ऐसी वर्षा को असमय वृष्टि कहते हैं। ऐसी वर्षा फसलों की बुवाई, अंकुरण पौधों की वृद्धि तथा पकाई और भंडारण जैसी सभी क्रियाओं पर बुरा प्रभाव डालती है। उपरोक्त क्रियाओं में से कोई सी क्रिया भी नियमानुसार पूर्ण नहीं होती है जिससे उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे-

(द्व) बुवाई से पूर्व वर्षा से दोबारा जमीन तैयार करने में समय लग जाता है जिससे फसल देर से बोई जाती है।

(ii) बुवाई के तुरंत बाद वर्षा होने से बीज के जमीन में सड़ने का भय रहता है तथा जमीन की ऊपरी सतह सूखकर कठोर हो जाती है जिससे अंकुरण नहीं होता है।

(iii) कई बार असमय वर्षा से खेतों

की निराई-गुड़ाई ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है जिससे खरपतवार अधिक उग जाती है।

(i1) फसल की पकाई के समय की वर्षा कई बार फसल को नष्ट कर देती है तथा उसकी कटाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(1) असमय वर्षा रबी तथा खरीफ की फसलों को खलियानों से उठाने में भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कई बार तो उपज का काफी हिस्सा नष्ट हो जाता है।

पाले का प्रभाव - आमतौर पर पाला दिसंबर तथा जनवरी के महीनों में पड़ता है। उस समय रबी की फसलें खेतों में होती है। पाला पड़ने पर पेड़ पौधों की कोशिका का जल बर्फ में बदल जाता है जिससे पेड़ पौधों की कोशिकाएं फट जाती है (क्योंकि पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में 1/5 भाग की वृद्धि हो जाती है।) जिसके कारण पेड़-पौधे सूख जाते हैं।

ओलों का प्रभाव - मार्च-अप्रैल के महीनों में होने वाली वर्षा में अधिकतर ओले पड़ जाते हैं क्योंकि इस मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 ? हो जाता है तो वायुमंडल का जल बर्फ में परिवर्तित होकर ओलों के रूप में बरसने लगता है जिससे खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है तथा जो फसलें पकी होती है उनके दाने खेतों में ही झड़ जाते हैं।

गर्म और तेज हवाओं का प्रभाव - मार्च-अप्रैल के माह में जब रबी की फसलों में दूध की स्थिति होती है तब दाने पकने से पूर्व गर्म तेज हवाओं के चलने से दानों का दूध सूख जाता है जिससे दानों का समुचित विकास नहीं हो पाता है तथा उपज कम हो जाती है।

फसलों पर प्रतिकूल मौसम के कुप्रभाव को दूर करने के उपाय -

फसलों को प्रतिकूल मौसम के कुप्रभाव से पूर्ण रूप से तो नहीं बचाया जा सकता है परंतु फिर भी बचाव के उपाय किए जाए तो फसलों को होने वाली हानि को काफी कम किया जा सकता है। फसलों को प्रतिकूल मौसम के कुप्रभाव से बचने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं-

त्रुटियुक्त वर्षा के कुप्रभाव से फसलों की सुरक्षा-

त्रुटियुक्त वर्षा के अन्तर्गत वर्षा की तीन अवस्थायें - (द्व) अनावृष्टि, (ii) अतिवृष्टि, (iii) असमय वृष्टि आती हैं। इन तीनों अवस्थाओं से फसलों का बचाव निम्नलिखित उपायों से कर सकते हैं-

अनावृष्टि से फसलों की सुरक्षा

अनावृष्टि की स्थिति में फसलों की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए -

01. जिन क्षेत्रों में अनावृष्टि (कम वर्षा) होती है वहां ऐसी फसलों की खेती करनी चाहिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है; जैसे - ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, मूंगफली, आदि।

02. ऐसे क्षेत्रों में कम पानी चाहने वाली तथा कम समय में पकने वाली फसलें उगानी चाहिए और शुष्क खेती की विधि प्रयोग में लानी चाहिए। शुष्क खेती विधि के द्वारा ऐसे यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे भूमि में पानी की अधिक से अधिक मात्रा बनी रहती है।

03. ऐसे क्षेत्रों में गर्मियों में जुताई अधिक की जाती है जिससे थोड़ी वर्षा होने पर भी जमीन में अधिक से अधिक नमी बनी रहती है।

04. ऐसे क्षेत्रों में खरीफ की फसल के बाद नमी को संरक्षित रखने के लिए जुताई के बाद पाटा अवश्य लगा देना चाहिए।

05. ऐसे क्षेत्रों में खरपतवार को नियंत्रित रखना चाहिए तथा मिश्रित फसलें उगानी चाहिए।

अतिवृष्टि से फसलों की सुरक्षा -अतिवृष्टि से फसलों की सुरक्षा निम्नलिखित उपायों के द्वारा की जा सकती है-

01. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अतिवृष्टि (अधिक वर्षा) होती है, खेतों से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अधिक समय तक खेतों में पानी न भरा रहे।

02. ऐसे क्षेत्रों में ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिनमे जल की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे - धान, गन्ना, आदि।

03. ऐसे क्षेत्रों में ऐसी फसलें (अगेती फसलें) उगानी चाहिए जो जल्दी पक जाती हैं तथा अतिवृष्टि से पूर्व ही उन्हें काटा जा सके।

04. जो खेत गहरे हों उनके जल पम्पिंग सेट की सहायता से निकाल देना चाहिए, जिससे पौधों की जड़े न गल पायें।

05. ऐसे क्षेत्रों में खरीफ की फसल काटने के बाद खेतों की उथली जुताई करके उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए जिससे खेत जल्दी सूख सके।

असमय वृष्टि से फसलों की सुरक्षा -

असमय वृष्टि से फसलों की सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं -

01. यदि फसल बोने से पूर्व पलेवा के बाद वर्षा हो जाये तो खेत को कल्टीवेटर से जुताई करके छोड़ देना चाहिए जिससे खेत शीघ्र ही जुताई के लिए सूख जाये।

02. यदि खेत की बुवाई के एक-दो दिन बाद ही वर्षा हो गई है और खेत में पपड़ी जम गई है तो ऐसी स्थिति में खूंटीदार पटेला से पपड़ी तोड़ देनी चाहिए, जिससे पौधे अंकुरित होकर बाहर निकल जायें।

03. फसल पकने के पूर्व यदि वर्षा हो गई है तो खेत के जल की निकासी का प्रबन्ध करना चाहिए।

04. यदि फसल काटने के बाद वर्षा हो जाये तो फसल को ऊँचे स्थान पर इस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि बालियाँ ऊपर की ओर रहें।

पाले से फसलों को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए-

फसलों को पाले की हानि से बचाने के लिए खेतों में पानी लगा देना चाहिए। खेतों में पानी लगा देने से भूमि के निकट की वायु का ताप हिमांक बिन्दु से अधिक ही रहता है जिसके फलस्वरूप पाले के स्थान पर ओस पड़ती है।

02. रात्रि में खेत पर जिस दिशा में वायु का बहाव हो उस मेंड़ पर धुआँ करना चाहिए जिससे सम्पूर्ण खेत में धुआँ फैल जाये तथा खेत का ताप बढ़ने से पाला नहीं पड़ेगा।

03. ,पुआल, घास तथा पॉलीथिन का पलवार (स्व्हृद्यष्द्ध) के रूप में प्रयोग करना चाहिए जिससे खेत की नमी सुरक्षित रहे तथा खेत का ताप हिमांक बिन्दु से ऊँचा बना रहे।

04. फसलों में ऐसी जातियाँ उगानी चाहिए, जो पाले को सहन कर सकें।

05. छोटे पेड़ों को पाले से बचाने के लिए उनके ऊपर घास-फूँस के द्वारा गोल घेरे के रूप ढककर बाँध देना चाहिए।

गर्म तेज हवाओं (लू) से फसलों की सुरक्षा -

जिस प्रकार से पाला फसलों के लिए हानिकारक है ठीक उसी प्रकार लू भी फसलों को हानि पहुँचाती है। लू से फसलों को बचाने के उपाय निम्नलिखित हैं -

01. ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो तेज गर्मी तथा लू को सहन कर सकें। जैसे- तरबूज, खरबूजा व ककड़ी आदि।

02. खेतों में घास-फूँस की पलवार का प्रयोग करना चाहिए जिससे भूमि में नमी बनी रहे।

03. तेज हवाओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों में पानी उस स्थिति में लगाना चाहिए जब हवा बंद हो, नहीं तो फसलों के गिरने का भय रहता है।

04. यदि झड़ने वाली फसल पक रही हो तो उसे खेत में झड़ने से बचाने के लिए एक-दो दिन पूर्व ही काट लेना चाहिए।

फसलों पर मौसम का अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव

भारतवर्ष की अधिकांश भूमि पर असिंचित खेती होती है जहां पर फसल का पैदा होना या ना होना केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर भी जहां सिंचाई के साधन है, यदि मौसम फसलों के अनुकूल है तो अच्छी उपज होती है इसके विपरीत मौसम के प्रतिकूल दशाएं होने पर उपज अच्छी नहीं होती है। हमारे देश में मुख्यत: 3 ऋतुएँ ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद की होती हैं। इन ऋतुओं का मौसम भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। इसी आधार पर भारतवर्ष में मुख्यत: फसलों को भी जलवायु के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-

खरीफ की फसलें- इन फसलों के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, महुआ, उर्द, लोबिया, अरहर, ग्वार, तिल, मूंगफली, कपास, सनई तथा पटसन आदि की खेती होती है। इन फसलों की बुवाई के लिए वायुमंडल का ताप ऊंचा होना चाहिए तथा वृद्धि के लिए अच्छी नमी तथा अधिक समय तक धूप की आवश्यकता होती है।

अर्थात दिन बड़े होने चाहिए तथा फसलों की पकाई के समय कम समय तक धूप की आवश्यकता पड़ती है अर्थात दिन पहले से छोटे होने चाहिए। यही कारण है कि इस श्रेणी की फसलों का समय जून से अक्टूबर तक होता है।

रबी की फसलें- इन फसलों के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, रिजका, गोभी, गाजर, मूली, आदि की खेती की जाती है। इन फसलों की बुवाई के समय वायुमंडल में अच्छी नमी कम धूप तथा हल्की ठंड की आवश्यकता पड़ती है। पौधों की वृद्धि के लिए ठंडा वातावरण तथा कम समय के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है तथा फसलों की पकाई के लिए गर्म दिन तथा अधिक समय के लिए धूप की आवश्यकता पड़ती है। इन फसलों की खेती का उपयुक्त समय नवंबर से अप्रैल तक होता है।

जायद की फसलें- इन फसलों के अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी, आदि की खेती की जाती है। इन फसलों की बुवाई के लिए हल्की ठंड और कम समय के लिए धूप की आवश्यकता होती है। वृद्धि एवं पकाई के लिए तेज गर्मी की आवश्यकता होती है।

सुरक्षित अन्न भण्डारण

अन्न उत्पादन में भारत एक अग्रणी देश है। हरित क्रांति के पश्चात् आई उत्पादन वृद्धि की बाढ़ ने हमें न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनाया अपितु निर्यात के क्षेत्र में भी हमें अद्वितीय पहचान दिलाई है। इतना प्रगतिशील होने के पश्चात् भी हमारे देश में अधिकांश अन्न का सुरक्षित भंडारण एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि अनाज का भंडारण, भारत का किसान, सदियों से करता चला आ रहा है, किन्तु फिर भी लाखों टन अनाज हर वर्ष खराब हो जाता है। सुरक्षित अन्न भंडारण की प्रक्रिया कटाई के साथ ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कटाई के लिए उपयोग में लाए गए यंत्र, वातावरण की परिस्थितियां (आर्द्रता और तापमान), प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्न के सुरक्षित भंडारण में अहम् भूमिका निभाते हैं

भंडारण की सुरक्षा और गुणवत्ता को हानि पहुँचाने वाले कारकों में सबसे प्रमुख है, कीड़ों का प्रकोप ये कीड़े बीज एवं मिट्टी के अतिरिक्त, गहाई या ढलाई में प्रयुक्त यंत्रों द्वारा भी भंडारण तक पहुँच सकते हैं। इस लेख में सुरक्षित अन्न भंडारण हेतु ध्यान देने योग्य कुछ कदम है।

1. सुरक्षित अन्न भंडारण से किसान को पैदावार का पूरा लाभ मिलता है।

2. सुरक्षित अन्न भंडारण करने से परिवार के लिए स्वच्छ एवं गुणवत्तायुक्त अनाज उपलब्ध होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कीड़ा लगा अनाज कई प्रकार की बीमारियाँ फैलाता है जैसे त्वचा से संबधित एलर्जी, अपच और अतिसार यानि स्वाद व स्वास्थ्य दोनो खराब।

3. सुरक्षित प्रकार से अन्न भंडारण करने पर किसान अपना बीज स्वयं तैयार कर सकता है, इस प्रकार उसे आर्थिक लाभ भी होगा।

4. यदि किसान अपने उत्पादन को मंडी में बेचना चाहता है, तो स्वस्थ फसल का भाव भी उसे अच्छा मिलता है।

5. अनाज में कीड़ों का प्रकोप हो जाने से किसानों का कार्य बहुत बढ़ जाता है, अन्न को साफ करने में कीड़ो से बचाने में किसानों को अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़ कर इस कार्य में लगना पड़ता है एवं दुगुना श्रम करने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है, कि सुरक्षित अन्न भंडारण का तरीका अपनाया जाए।

अनाज में संक्रमण व खराब होने के चार मुख्य कारण होते है, जैसे- नमी, कीट, चूहे तथा भंडारण के पात्र या बोरे।

नमी- अनाज के अन्दर की नमी तथा वातावरण की नमी दोनो की अधिकता अनाज को खराब कर सकती है। ज्यादा नमी होने से अनाज में कीड़ो का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि नमी में कीट और फफूंद की वृद्धि आसान होती है। नमी से अनाज गल या सड़ जाता हैं, या अंकुरित हो जाता है। नमी के कारण अनाज के दाने जुड़ भी सकते है, इन सब कारणों से अनाज की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है तथा संक्रमित अनाज खाने योग्य नहीं रहता है।

कीट- अनाज पर पलने वाले कीट खेत में ही अनाज के दानों पर अंडे देना शुरू कर देते है। कुछ समय बाद इन अण्डों से लट या इल्ली निकलकर अनाज को खाने लगती है। कीड़े अनाज के भंडार में अनाज के साथ रहने लगते हैं एवं अनाज को धीरे-धीरे अन्दर बाहर से खाकर खोखला कर देते है। ऐसा अनाज बोने तथा खाने लायक नहीं रहता है। इसलिए अनाज की कटाई से पहले ही सावधानियाँ रखनी शुरू कर देनी चाहिये।

चूहे- चूहे मनुष्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य सामग्री को काफी नुकसान पहुंचाते है। ये खड़ी फसल व भंडारित अनाज को जितना खाते है, उससे दस गुना बर्बाद करते है। चूहों के मल, मूत्र और बाल अनाज में मिल जाने से अनाज खराब हो जाता है। इसलिए चूहा नियंत्रण अन्न भंडारण का एक महत्वपूर्ण भाग हैं।

भंडारण के पात्र व बोरे- यदि भंडारण

में प्रयोग होने वाले पात्रों में दरारे हैं, तो उनमें कीड़े अन्डे दे देते है, जिससे नये कीड़ो का प्रकोप हो जाता है। यदि पुराने बोरों को प्रयोग किया जाता हैं, उसमें भी कीड़े या उनके अंडे हो सकते है।

अनाज में लगने वाले चार मुख्य कीट है चावल का घुन, गेहूं का खपरा, दालों का भुंग, आटे की सुंडी इन कीटों से प्रभावित होने वाले अन्न इस प्रकार है, जैसे-

चावल का घुन- चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार आदि।

गेहूं का खपरा- गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि।

दालों का भृंग- अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मोठ, चंवला आदि।

आटे की सुंडी- गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ज्वार, आटा, सूजी, मैदा आदि।

सुरक्षित अन्न भंडारण से होने वाले लाभ को देखते हुए सुरक्षित अन्न भंडारण आवश्यक है, जो आप इस प्रकार कर सकते है, जैसे-

अनाज की सफाई- अनाज की कटाई के साथ ही उसके सुरक्षित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती हैं, बाजरा, गेहूं, मक्का, ज्वार इत्यादि के सिट्टे व बालियाँ जिस बोरे में भर कर रखने हो उस बोरे को पहले से ही एक प्रतिशत मैलाथियॉन के घोल में 10 मिनट भिगो कर अच्छी तरह सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ो का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। काटे हुए अनाज को सीधे जमीन पर न रखे, इससे कीड़े तथा नमी दोनो से अनाज प्रभावित होगा।

अनाज लाने वाली गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रोली को अनाज रखने से पहले धो कर सुखा लेना चाहिये। अनाज खेत से लाकर घर में कड़ी धूप में सुखाना चाहिये, सुखाते समय प्लास्टिक का मोम जामा काम में ले जो कि भली भांति कीटनाशक से उपचारित होना चाहिये। भंडारण से पहले अनाज को साफ करें, उसमें से भूसी, कटा फटा अनाज, संक्रमित अनाज, कंकर इत्यादि निकाल दें, अनाज को करीब 15 से 20 दिन सुखाना आवश्यक है।